● वर्ष-4
● अंक-44
रायपुर, शनिवार
28 सितंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6»»» शरीर में पानी की कमी को हल्के में...

नवा रायपुर योजना में एनआरडीए को झटका!

500 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों की बड़ी जीत

बिलासपुर. नया रायपुर के 500 एकड़ जमीन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है. कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार और एनआरडीए को अपनी रणनीति बदलनी होगी और किसानों के साथ बातचीत करनी होगी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नया रायपुर की योजना भी खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में देरी हो सकती है. योजना की लागत बढ़ सकती है. किसानों की सहमति के बिना योजना आगे नहीं बढ़ सकती. किसानों ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाता है. वहीं एनआरडीए ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. सूत्रों के अनुसार, एनआरडीए इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.

नवा रायपुर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह तो एक रीको गांव पर आया फैसला है. नवा रायपुर के हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण से संबंधित करीब 96 याचिकाएं कोर्ट में लगी है. किसानों की अन्य याचिकाओं पर अभी फैसला बाकी है. हमने तो कई बार सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से अभी बातचीत नहीं हो रही है. भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने पर्यावास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात भी की थी. मंत्री ने जल्द ही बैठक करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई बैठक नई सरकार के साथ नवा रायपुर के किसानों की नहीं हुई है. उम्मीद है हाईकोर्ट के रास्ते ही किसानों की मांग और समस्याओं पर निर्णय होगा.

फैसले की प्रमुख बातें

1. पुराने भू अर्जन अधिनियम के तहत शुरू की गई प्रक्रियाओं पर भी नए कानून का प्रभाव पड़ेगा।
2. धारा 6 का प्रकाशन 01/01/2014 से पहले किया गया था, तो भू अर्जन अवार्ड एक वर्ष के भीतर करना था।
3. समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य हो जाएगा।
4. एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति जरूरी है।

21 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार जा रहे नड्डा

नई दिल्ली। सियासत में जो ऊपर से दिखता है, वह अंदर से भी वैसा ही हो, इसकी गारंटी नहीं है। राजनीतिक दंगल में कई बार जो चीजें सामने होती हैं, भीतर ठीक उसके विपरीत भी रह सकती हैं। कुछ वैसी ही स्थिति बिहार में दिखाई दे रही है। भले ही जदयू और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक-ठाक होने का दावा किया जा रहा है। सरकार मजबूती से चलाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आ रही। सवाल यह है कि तालमेल की कमी है या फिर जदयू और भाजपा के हाथ तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव अगले साल होने है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा और जदयू में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है।

लोगों के इस शक को मजबूती तब मिली जब यह खबर सामने आती है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 सितंबर को पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि नड्डा जी तो अभी ही बिहार का दौरा किए थे, फिर अचानक फिर क्यों से आ रहे हैं? 21 दिनों के भीतर भाजपा

अध्यक्ष के दूसरी बार बिहार दौरे को लेकर अटकलें का दौर शुरू हो गया है। वाकई कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है या महज यह संयोग है? इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। इसके कई उदाहरण भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सरकारी कार्यक्रमों में भाजपा और जदयू के रिश्तों में जो तनातनी है, वह साफ तौर पर सामने आई है। कुछ कार्यक्रमों में भाजपा के मंत्री मौजूद रहते हैं तो जदयू के मंत्री गायब होते हैं और जिन कार्यक्रमों में जदयू के मंत्री रहते हैं वहां भाजपा के मंत्रियों की अनुपस्थिति दिख जाती है। उदाहरण के तौर पर 19 सितंबर को बापू सभागार में वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यक्रम को बताया जा रहा है जिसमें राज्यपाल के अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरील विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। लेकिन जदयू के नेता एक भी नहीं थे। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी उसी दिन एक्सप्रेसवे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। लेकिन विभाग के मंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा उस बैठक से दूर रहे। नवादा कांड को लेकर भी नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक बुलाई थी जिसमें भाजपा नेताओं की दूरियां बरकरार रही। राजद भी अब इसको लेकर मजे लेने की कोशिश कर रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेपी नड्डा बिहार क्यों आ रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। जदयू और भाजपा के बीच मतभेद है। बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिनमें दोनों पार्टियों की राय बिल्कुल लग रही है। मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में दोनों पार्टी के नेता मौजूद नहीं हो रहे हैं। सीएम जब जहानाबाद गए थे तो भी वहां बीजेपी के नेता मौजूद नहीं रहे। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है और जेपी नड्डा डैमेज कंट्रोल के लिए पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि जदयू ने इसे पूरी तरीके से खारिज किया है और कहा है कि राजद कैसे कह सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है।

देश में राजनीति का मतलब सिर्फ 'सत्ता की राजनीति' है- गडकरी

छत्रपति संभाजीनगर । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति वास्तव में समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और विकास का पर्याय है, लेकिन वर्तमान समय में इसका मतलब केवल सत्ता की राजनीति है। उन्होंने कहा, ''राजनीति में विचारों में मतभेद की समस्या नहीं, बल्कि विचारों की कमी की समस्या है। राजनीति का अर्थ है 'समाजकरण (समाज सेवा), राष्ट्रकरण (राष्ट्र निर्माण) और विकासकरण (विकास)'। लेकिन अब राजनीति की परिबदलकर 'सत्ताकरण (सत्ता की राजनीति)' ही रह गई है।'' गडकरी ने कहा, ''पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ता के रूप में काम करते समय, हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कोई पहचान और सम्मान नहीं था। हरिभाऊ बागड़े ने लोगों के कल्याण के लिए समर्पण के साथ काम किया...मैंने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में 20 वर्ष तक विदर्भ की यात्रा की और काम किया।'' उन्होंने कहा, ''लोग हमारी रैलियों पर पत्थर फेंकते थे। आपातकाल के बाद जिस ऑटोरिक्शा का इस्तेमाल मैं घोषणाएं करने के लिए करता था, लोगों ने उसे जला दिया था।'' गडकरी ने कहा कि पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता वही होता है, जो पार्टी में कुछ न मिलने पर भी अच्छा व्यवहार करता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें कुछ मिलता है,वे स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार करते हैं।

लालू और परिवार ने रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के जरिए अवैध फायदा उठाया

नई दिल्ली। जमीनों के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में ईडी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भारतीय रेलवे में नियुक्तियों के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीनें लेने का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी तलब किया था। जबकि तेज प्रताप को जांच

एजेंसी ने आरोपी के रूप में नामित नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि अदालत को प्रथम दृष्टया और सम्मन के चरण में पता लगा है कि तेज प्रताप यादव भी अपराध की आय के अधिग्रहण और छिपाने में शामिल थे। इसलिए वह भी शिकायत पर सम्मन किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। कोर्ट ने प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी तलब किया। न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और अन्य को सात अक्तूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को तलब किया था। वहीं ईडी ने चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव पर अपराध की आय को छिपाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जमीनें इस तरीके से लीं, जिससे उनकी भागीदारी सामने न आए और परिवार को लाभ हो सके। जब प्रसाद रेल मंत्री थे तब मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरियों के वादे के साथ कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए राजी किया गया था। ईडी ने कहा कि इनमें से कई जमीनें पहले से ही यादव परिवार के पास मौजूद जमीनों के पास थीं। सात में से छह जमीन के सौदे राबड़ी देवी से जुड़े थे.

प्रमुख समाचार

ब्रह्मोस एयरोस्पेस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

नई दिल्ली। और रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों को कंपनी में नौकरियां आरक्षित करने का ऐलान किया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने टेक्निकल एंट्रीज में 15 प्रतिशत और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं में रिक्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारतीय सशस्त्र बलों की अग्निपथ योजना के तहत नए भर्ती हुए अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देगी। ये आरक्षण उन पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा, जिन्होंने सेना में चार साल तक नौकरी की होगी। ब्रह्मोस एयरोस्पेस अपने अलग-अलग क्षेत्रों में कम से कम 15 फीसदी तकनीकी और सामान्य प्रशासन वैकेंसी में अग्निवीरों को भर्ती करेगा। यही नहीं कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि देशभर में अपने अलग-अलग सेंटरों पर आउटसोर्स किए गए सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए कम से कम 50 फीसदी रिक्तियां अग्निवीरों द्वारा भरी जाएंगी।

हिमाचल स्ट्रीट वेंडर विवादः पार्टी की विचारधारा का करें पालन

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंत्री

विक्रमादित्य सिंह द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा नाम प्रदर्शित करने को अनिवार्य करने संबंधी टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को उन्हें फटकार लगाई और कहा कि किसी को भी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव, प्रभारी संगठन, केसी वेणुगोपाल ने यहां विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक की, जिसके दौरान मंत्री को बताया गया कि पार्टी राहुल गांधी के नफरत से प्यार से लड़ने के मंत्र में विश्वास करती है, जबकि विक्रमादित्य सिंह से कहा गया कि उन्हें पार्टी की विचारधारा और नीतियों का पालन करना चाहिए, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताया कि मीडिया ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया है। स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा नाम प्रदर्शित करने को अनिवार्य करने संबंधी विक्रमादित्य सिंह की घोषणा पर आलोचनाओं का सामना कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चुनाव चिह्न दिलाने तक जारी रहेगी लड़ाईः सुप्रिया सुले

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा कि उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह अपने पिता शरद पवार की बनाई पार्टी और चुनाव चिह्न उन्हें वापस नहीं दिला देतीं। शरद पवार की पार्टी राकांपा पिछले साल जुलाई में उस समय टूट गई थी। जब सुले के चचेरे भाई अजित पवार और आठ विधायक एकनाथ शिंदे सरकार की सरकार में शामिल हो गए थे। इस टूट के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न घड़ी दे दिया था। जबकि शरद पवार के गुट का नाम राकांपा (एसपी) रखा गया और उसे चुनाव चिह्न तुतारी बजाता हुआ आदमी दिया गया। उत्तर पूर्व मुंबई के अणुशक्ति नगर में महा विकास अघाड़ी की रैली को संबोधित करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जब तक मैं पवार साहब को उनकी बनाई पार्टी और उनका चुनाव चिह्न नहीं दे देती, तब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि, उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें नवाब मलिक से एलर्जी थी। मलिक अणुशक्ति नगर से मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ अपना समर्थन जताया था।

भाजपा जम्मू में आतंकवाद के फिर उभार के लिए जनता से माफी मांगे

उधमपुर/जम्मू । नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपेक्षाकृत शांत रहने वाले जम्मू संभाग में हाल में हुए आतंकवादी हमले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथित नाकामी दिखाते हैं और पार्टी को जम्मू-कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के लिए नेकां, कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को जिम्मेदार ठहराकर पाकिस्तान को 'क्लीन चिट' दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद की क्या स्थिति है जहां हमारे बहादुर बल के जवानों को अक्सर निशाना बनाया जाता है? भाजपा को पहले जवाब देना चाहिए कि 2014 के बाद जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद क्यों फैला, खासकर पिछले तीन वर्षों में जब हमले बढ़े हैं।'' उन्होंने कहा, ''जम्मू का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आतंकवादी हमले नहीं हुए हों, फिर चाहे चिनाब घाटी हो, पीर पंजाल क्षेत्र हो यारियासी, कठुआ,उधमपुर, जम्मू और सांबा हो... यह उनकी (भाजपा सरकार की) नाकामी को प्रतिबिंबित करता है और पार्टी को इसे स्वीकार कर जनता से माफी मांगनी चाहिए।''

भाजपा के पास स्थाई समिति में बहुमत- वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की आज दिल्ली नगर निगम सदन से स्थाई समिति के चुनाव के बाद स्थाई समिति का गठन पूर्ण हो गया है और अब अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी को स्थाई समिति अध्यक्ष के चुनाव को और अधिक बाधित नही करना चाहिए ताकि दिल्ली नगर निगम के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय हो सकें। सचदेवा ने कहा है की कूड़ा लैंडफिल साइट ठेकों से लेकर डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण योजना तक ना जाने कितने जरूरी काम स्थाई समिति ना होने से अटके हैं और अब जब भाजपा के पास स्थाई समिति में बहुमत है तो हम यह सभी अति आवश्यक काम तुरंत पूरे करना चाहते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की हठधर्मी के चलते दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति सदस्य का चुनाव निगम में आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा बन गया था और भाजपा ने इसको जीत कर लोकतंत्र की रक्षा की की है। हमारा स्थाई समिति चुनाव लड़ने का लक्ष्य केवल हार जीत नही बल्कि स्थाई समिति का गठन करवा कर जनसेवा कार्य शुरू करवाना था।

सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देने से ही समाज स्वस्थ और सुखी होगाः डॉ. मुरुगन

आबू रोड। ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान के आबू रोड स्थित मुख्यालय शांतिवन के आनंद सरोवर परिसर में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन और मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया। मीडिया विंग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण- मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए देशभर से एक हजार से अधिक प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, रेडियो और बेव जर्नलिज्म से जुड़े पत्रकार, संपादक, ब्यूरो चीफ, रेडियो जॉकी, फ्रीलांसर पत्रकार और मीडिया प्रोफेसर पहुंचे हैं।

शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरुगन ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। आज एक अच्छी न्यूज उतनी तेजी से वायरल नहीं होती है जितनी की एक गलत, फेंक न्यूज़ वायरल हो जाती है। पत्रकार पहले खबरों की सत्यता की जांच कर लें उसके बाद ही प्रकाशित करें। अच्छी खबरों को बढ़ावा देने से ही स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण होगा। आज समाज में यदि नकारात्मक माहौल बन रहा है तो हमें चिंतन करने की जरूरत है कि हम समाज में क्या भेज रहे हैं। मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के लिए हमें जीवन में मूल्यों का समावेश करना होगा।

पत्रकार निजी जीवन में अध्यात्म को अपनाएं - उन्होंने कहा कि एक पत्रकार का मौलिक अधिकार है कि वह आध्यात्मिकता से जुड़े। मीडियाकर्मी अपने निजी जीवन में अध्यात्म को अपनाएं। एक पत्रकार

गलत न्यूज़ से देश का माहौल बिगाड़ सकता है इसलिए पत्रकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सूचना देने के लिए मीडिया सबसे शक्तिशाली साधन है, जो दुनिया को खेल और संस्कृति आदि की जानकारी देता है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया हिमालय से लेकर रेगिस्तान में जाकर सूचनाएं जुटाता है।

ब्रह्माकुमारीज़ विश्व शांति के लिए कार्य कर रही है - केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरुगन ने कहा कि विश्व शांति के लिए ब्रह्माकुमारीज़ संस्था कार्य कर रही है। मैं पहली बार ब्रह्माकुमारीज़ के मुख्यालय आया हूं। यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और बहुत खुशी हो रही है। मैंने दादी रतन मोहिनी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। यहां की दिव्यता और पवित्र माहौल बहुत सुखदायी है।

मीडिया अपने उद्देश्य से भटक गया है- डॉ. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवम जनसंचार विश्विद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉ. मान सिंह परमार ने कहा कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो मीडिया के सामने एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य था। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो मीडिया के सामने एक चुनौती थी कि अब किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन आज व्यापारवाद के दौर में मीडिया अपने उद्देश्य से भटक गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जो किसी भी रीति से समाज के लिए ठीक नहीं है। सोशल मीडिया ने हमें आजादी जरूर दी है लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं सोशल मीडिया भस्मासुर न बन जाए। प्रेस काउंसिल बने वर्षों हो गए लेकिन आज तक हम एक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं कर पाए हैं।

नई दिल्ली दैनिक जागरण के एक्जीक्यूटिव एडिटर विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता के स्तंभ हैं। हम सत्यनिष्ठ लोग हैं। लोकतंत्र में संरक्षण की जरूरत है लेकिन यदि मीडिया को नियंत्रीकरण किया जाएगा तो वह अपना अस्तित्व खो देगा। भारत का पत्रकार आध्यात्मिक ही होगा। दिल्ली के पीआईबी के पूर्व प्रिंसिपल डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि कई बार हम पत्रकारों को अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन हमें अपने मूल्यों को कायम रखना होगा।

अश्लील सामग्री मुक्त मीडिया बनाना होगा - आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि हम सभी पत्रकारों को अभियान चलाना चाहिए कि अश्लील सामग्री मुक्त समाज बने। हमें अश्लील कंटेंट को प्रचारित और प्रसारित करना बंद करना होगा। एक-एक व्यक्ति सूचना का राजदूत है। ब्रह्माकुमारीज़ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य कर रही है। ये ब्रह्माकुमार भाई-बहनें त्याग की मूर्ति हैं। दुनिया के बेहतर अखबारों को टक्कर देने वाले अखबार आज हमारे देश में निकल रहे हैं। आज मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है। आज हम जिस मीडिया की तर्ज पर कार्य कर रहें हैं, वह पाश्चात्य मीडिया की शैली है। हमारे यहां तो लोक मंगल की भावना को लेकर कार्य करने की परंपरा रही है। हमें संवाद की परंपरा की ओर फिर से बढ़ने की जरूरत है। हम जगतगुरु की बात कर रहे हैं लेकिन कोई शिष्य बनने के लिए तैयार है।

कथित फर्जी मुठभेड़ के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

■ थाने के सामने निकाली रैली

सुकमा। सुकमा में बीते दिनों करकनगुड़ा इलाके में हुए सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद 500 से अधिक ग्रामीण चिंतलनार में थाने के सामने प्रदर्शन और रैली करते नजर आए । बता दें कि पुलिस की से मुठभेड़ बता रही है उसे पर ग्रामीण फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं ग्रामीणों का आरोप है कि रोजमर्रा की जरूरत के लिए निकले ग्रामीणों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाकर हमला किया गया जिसमें एक ग्रामीण की गोली लगने से मौत हो गई। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि दो ग्रामीणों को नक्सली बताकर सुरक्षाबल के जवान अपने साथ लेकर गए थे।

मामला 24 सितंबर का है जहां पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कर्कनगुड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें तीन नक्सलियों के मारे जाने का दावा पुलिस के द्वारा किया गया था और यह लिखा गया था कि जंगलों की आड़ में ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच नक्सली अपने साथी नक्सलियों के शवो को ले जाने में सफल हो गए । इसके बाद भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामग्री की तस्वीर भी पुलिस के द्वारा जारी की गई थी। नक्सली संगठन ने मछली पकड़ने गए ग्रामीण की हत्या का लगाया आरोप।

बता दें कि इस मामले पर नक्सलियों की दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी सचिव गंगा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें सुरक्षा बलों पर आरोप लगाते हुए नक्सली संगठन ने लिखा है कि 24 सितबंर तड़के चिंतलनार थाना व पुलनपाड़, मुकरम, बुरकापाल कैम्पों से सीआरपीएफ, कोब्रा, बस्तर फायटर्स, डीआरजी सशस्त्र बलों ने 1,000-1,500 के तादाद में बड़े मोरपल्ली, बंडा मोरूम, गोलागूडा, करकानगूड़ा गांवों में सैन्य अभियान संचालित कर ग्राम करकानगूड़ा के ऊपर तड़के 3 बजे हमला किये. हमले के वक्त कुछ ग्रामीण हर दिन कि तरह मछली शिकार के लिए जाकर चिंतावागु नदी किनारे सोये थे. सशस्त्र गुंडा बलों ने सोये हुए इन ग्रामीणों को नाटकीय ढंग से तेदार कॉमरेड (उठो कॉमरेड) ऐसा कहते हुए ग्रामीणों को खुद चेताकर उनके ऊपर गोलियां बरसायी गई. एक ग्रामीण कवासी भीमा ने जान बचाने के लिए भागते वक्त गोलियां खाकर नदी में जाकर गिर पड़ा. इसका लाश ग्रामीणों ने घंटों तालाशी के बाद पाकर गांव में लेके आया और एक ग्रामीण इस गोली बारी से किसी तरह भागकर जान बचा सका. अन्य दो ग्रामीण कवासी बंडी, माड़वी भीमा को इन गुंडा बलों ने हाथ बांधकर अपने साथ ले गये. इस जघन्य हत्या को मुठभेड़ के रूप में दिखाने के लिए पुलिस बलों द्वारा जंगलों में अंधाधुंध सेलिंग भी कि गई हैं।

इसकी चपेट में आकर ग्राम मोरपल्ली के एक ग्रामीण भी घायल हुये है । इतना फाशविक तरिके से एक निर्मम हत्ये को अंजाम देकर उल्टे मे इसे हमारे गेरिला बटालियन के साथ चली एक कथित मुठभेड़ के रूप में दिखाने में भाजपा तथा सशस्त्र गुंडा बलों कि विफल प्रयासे उनके अत्यंत फाशविक हिंसा प्रवृत्ति को साफ तौर पर दर्शाती है । माड़वी भीमा से 15 हजार रुपया लूट लूटने का भी आरोप लगाया है। पुलिस बलों द्वारा पकड कर ले गये उक्त ग्रामीणों को छुड़ा लाने जा रहे मड़काम भीमें, मड़काम देवे और अन्य ग्रामीण महिलाओं से पुलिस बलों द्वारा बेरहमी से मार-पीट की गयी मड़काम देवे को पुलिस बलों द्वारा मारने कि कोशिश भी की गई. लेकिन इस बच्चे कि माँ को मारने के बारे में उन्हीं के बीच हुई आपसी वाद-विवाद के चलते आखिरकार उसे छोड़ गया। 23 सितबंर को सिलंगेर, टेकलगूड़ा कैंपों से सशस्त्र बलों ने टेकलगुड़ा, जोन्नागूड़ा, अल्लीगूड़ा गांवों पर रातों-रात घेर कर हमला की. जोन्नागूड़ा गांव से 5 आम ग्रामीणों को बेदम पिटाई कर पूर्नम लखमा, अवलम इंगा, ओयम पांडू, अवलम सुक्कू, काम अर्जून को अपने साथ ले जाने और गांव में हमले के वक्त जनता का साजो-सामान भी पुलिस बलों ने लूट कर ले जाने का भी आरोप लगाया है।

पुनर्वास योजना का फर्जी तरीके से लाभ पाने नक्सली बनकर आत्मसमर्पण करने पहुंचा युवक

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अनोखा मामला सामने आया है, जहां सरकार की पुनर्वास नीति योजना का लाभ लेने बेरोजगार युवक अपने आपको नक्सली बताकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार हाथ में हथियार थामें नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने लोन वर्राटू अभियान चला रही है। इसके तहत नक्सली विचारधारा को छोड़ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की ओर से सहायता राशि व अन्य सुविधाएं दी जा रही है। इन्हीं योजनाओं का लाभ पाने की मनसा लिए बीजापुर जिले के रहने वाला बेरोजगार युवक बबलू उर्फ (मधु मोड़ियाम) अपने रिश्तेदार सुदेश उर्फ मनकू और मानपुर मोहला क्षेत्र के रहने वाले एक साथी ओमप्रकाश नेताम के साथ बालोद पहुंचा और पुलिस के समक्ष अपने आपको मानपुर मोहला कमेटी का नक्सली सदस्य बताकर कई नक्सली घटना में शामिल होने की बात कहते हुए आत्मसमर्पण करने की बात कही।

बालोद एडिशनल एसपी अशोक कुमार जोशी ने बताया, बीजापुर के बबलू के साथ आए दो युवक उन्हें नक्सली साबित करने में लगे रहे। जब पुलिस मामले की छानबीन की तो पता चला कि बबलू उर्फ (मधु मोड़ियाम) की नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है, बल्कि पुलिस को गुमराह कर पुनर्वास नीति योजना से मिलने वाली राशि व अन्य लाभ लेकर आपस में बांटने की योजना बनाकर नक्सली साबित करने पर तुला है। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ 319(2), 6 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

जिले के सभी दफ्तरों में कामकाज ठप्प राजस्व कोर्ट में आज की पेशी बढ़ीं

बेमेतरा। जिले के सभी कर्मचारी-अधिकारी आज शुक्रवार को हड़ताल पर हैं। इनने मास्टर, बाबू, पटवारी, तहसीलदार,डिप्टी कलेक्टर और सफाईकर्मी से लेकर ड्राइवर तक शामिल हैं। दरअसल, यह हड़ताल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हो रहा है। आज जिले में कलेक्टर को डीए सहित विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बेमेतरा जिले के सभी दफ्तरों में कामकाज ठप्प है। राजस्व कोर्ट के आज जितनी पेशी थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। सरकारी अस्पताल में भी ग्रामीण पुरुष व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आज ड्यूटी पर नहीं गए है। ये सामूहिक अवकाश लिए हुए।पटवारी, शिक्षक समेत अधिकांश कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है।

फेडरेशन के नेताओं ने बताया कि प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरी तरह फेल हो चुकी है। यहां कर्मचारियों की मूल मांगे तो दूर डीए जैसे मूलभूत चीजें भी नसीब नहीं हो पा रही है। जबकि नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी कहकर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों से बहुत सारे वादे किए थे। साथ ही यह भी कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जब जब बढ़ेगा तब तब राज्य कर्मचारियों का भी डीए तत्काल बढ़ाया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। आज हमे डीए जैसे पूरक, छोटी एवं अनिवार्य मांगो के लिए भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इस एकदिवसीय हड़ताल में पूरे प्रदेश के कर्मचारी शामिल हैं।

ये हैं मुख्य मांगें -

1. केंद्र सरकार के समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए और जुलाई 2019 से देय महंगाई भत्ते के एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। 2. घोषणा पत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए। 3. केंद्र सरकार के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। 4. मध्यप्रदेश सरकार की तरह, शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण 240 दिनों के बजाय 300 दिनों के लिए किया जाए।

छत्तीसगढ़ में कलम बंद हड़ताल, डीए एरियर समेत चार सूत्रीय मांगें

भिलाई। राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी आज एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आह्वान छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने किया है, लेकिन स्थानीय नगर निगम और पालिका में छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ और कर्मचारी कांग्रेस ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया।

भिलाई और दुर्ग सहित भिलाई चरोदा और रिसाली नगर निगम में शुक्रवार को कार्यालयीन कामकाज ठप रहा। ऐसी ही स्थिति जामुल और कुम्हारी सहित जिले के अन्य नगर पालिकाओं में बनी रही। निकाय कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने के लिए एक दिन का अवकाश ले रखा था। वहीं निकाय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान कर्मचारियों अधिकारियों से चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की गई।

हड़ताल से आवश्यक सेवाओं को अलग रखा गया- छत्तीसगढ़

स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शरद दुबे बताया कि फेडरेशन की चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में भिलाई निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले सरकारी कर्मचारियों से उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था। अगर सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेगा। प्रदेश के 33 जिलों और 146 विकासखंडों में कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है।

शरद दुबे ने कहा फेडरेशन ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर 50 प्रतिशत डीए स्वीकृत करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किए जाने की मांग है।

फेडरेशन ने मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने के स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। दूसरे चरण में 20 से 30 अगस्त 24 तक सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया। तीसरे चरण में 11 सितंबर को जिला, ब्लॉक व तहसील में मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। चौथे चरण में 27 सितंबर को प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी ने अवकाश में रहकर कलम बन्द हड़ताल किया है।

एनएसयूआई ने प्रतीक सिंह को डीयू के छात्र संघ चुनाव में दी बड़ी जिम्मेदारी

बलरामपुर रामानुजगंज। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में नगर के वार्ड क्रमांक चार निवासी एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव एवं तेलंगाना एनएसयूआई प्रभारी प्रतीक सिंह उर्फ हैप्पी को महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। बीते 20 दिनों से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रागिनी नायक, कन्हैया कुमार, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित अन्य नेताओं के सतत मार्गदर्शन में दिल्ली नार्थ कैम्पस के महाविद्यालय में एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशियों को जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रतीक सिंह ने बताया कि बीते 20 दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर कार्य कर रहा हूं। नॉर्थ कैंपस के दर्जनों कॉलेज में एनएसयूआई समर्थित छात्र संघ के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार की महत्वपूर्ण जवाबदारी संभाल रहा हूं। तेलुगू स्टूडेंट एसोसिएशन एवं पूर्वांचल छात्रों का सम्मेलन भी मेरे नेतृत्व में आयोजित कराया गया। प्रतीक सिंह ने बताया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रागिनी नायक व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ कार्य करने एवं बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। प्रतीक सिंह के द्वारा पिछले वर्ष भी 39 दिन दिल्ली में रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था जिसके लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा सराहना मिली थी। पटना विश्वविद्यालय चुनाव में ऑब्जर्वर भूमिका भी निभा चुके हैं प्रतीक सिंह।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एनआईए स्थापित करेगा विशेष न्यायालय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अब राजनांदगांव और अंबिकापुर में भी विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए कदम के तहत जनवरी 2021 में जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है और बिलासपुर स्थित एनआईए का विशेष न्यायालय पूर्व की तरह ही कार्य करता रहेगा। राज्य सरकार ने राजनांदगांव और सरगुजा में एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया गया है। राजनांदगांव के एनआईए कोर्ट में राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, और कबीरधाम जिलों से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई होगी। बिलासपुर के एनआईए विशेष न्यायालय में प्रदेश के शेष जिलों से जुड़े एनआईए के मामले सुने जाएंगे।

36 घंटे की बारिश से जशपुर में बाढ़ के हालात

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पिछले 36 घंटे से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बगीचा से कलिया की ओर जाने वाली मार्ग पर पुलिया बहने से कई गांव का संपर्क जिला और ब्लाक मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं मवेशी चराने गए दो व्यक्ति और महिला समेत तीन लोग 24 घंटे से टापू में फंसे हुए हैं। लगातार बारिश से बगीचा स्थित प्रसिद्ध राजपुरी जलप्रपात भी उफान पर है। बगीचा से कलिया की ओर जाने वाली मार्ग पर पुलिया बहने से आवाजाही ठप हो गया है। फरसाबहार क्षेत्र के बाबुसाजबहार गांव में इब नदी का जलस्तर बढ़ने से मवेशी चराने गए तीन लोग टापू में फंसे हुए हैं। 24 घंटे से भूखे प्यासे नदी के पार फंसे हैं। तीनों ने पूरी रात खुले आसमान में टापू पर बिताया। जानकारी के मुताबिक, कल सुबह 9 बजे महिला समेत तीन लोग मवेशी चराने गए थे। लगातार बारिश से इब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे तीनों लोग टापू पर फंस गए। रेस्क्यू के लिए आज टीम मौके पर पहुंची है।

हाथियों का आतंक, ग्रामीण को फिर उतारा मौत के घाट

राजिम। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर क्षेत्र ने

हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के हमले से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक, तड़के सुबह 3 बजे सोरीदखुर्द निवासी कुमार मरकाम उम्र 44 वर्ष फुटु तोड़ने गया था, तभी तीन हाथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही ग्रामीण की मौत हो गई। यह घटना फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के ग्राम बनगवा की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने हाथियों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। इसके बाद भी ग्रामीण हाथी की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही फिंगेश्वर वन अमला सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि महीनेभर पहले छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हाथी के हमले में चार लोगों की मौत हुई थी। सड़क किनारे एक घर में हाथी ने धावा बोलते हुए घर में सो रहे 6 लोगों पर हमला किया था। इस घटना में पिता-पुत्री और चाचा समेत एक पड़ोसी की मौत हुई थी।

डिप्टी रेंजर पर जानलेवा हमला करने के बाद बंधक बनाया

कवर्धा। डालमौहा गांव के वन विकास निगम परिक्षेत्र के कूदूर नाला में 22/23 सितंबर की दरमियानी रात रेत माफिया और उनके गुर्गे बड़ी संख्या में जेसीबी से रेत का अवैध खनन कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर गणेश चन्द्रवंशी और अनील कुर्रे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रेंजर ने अवैध खनन को रोका और गाड़ियों की जब्ती कार्रवाई करने लगे। इसी दौरान रेत माफिया और उनके गुर्गे अधिकारियों पर टूट पड़े और लाठी डंडों से पिटाई चालू कर दी। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर अधिकारी, कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने डिप्टी रेंजर गणेश चन्द्रवंशी और अनील कुर्रे को पकड़ लिया और लाठीडंडों से खूब पीटा। हमले में दोनों अधिकारियों की वर्दी भी फाड़ी दी और बेरहमी से मारपीट किया। इस हमले में दोनों रेंजर्स के सिर पर गंभीर चोट आई और दोनों बेहोश हो गए।आरोपी यही नहीं रुके और अधिकारियों को जेसीबी में डालकर 6 किलोमीटर दूर गांव लेकर पहुंचे और उन्हें बंधक बनाकर रखा।

हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट का फैसला

कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या

के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है। दोषी का नाम बीसूराम बैगा पिता भरोसा बैगा उम्र 51 निवासी ग्राम साजाटोला थाना जंगल तरेगांव है। मामला 9 नवंबर 2023 का है। दोषी ने बीसूराम ने आपसी विवाद के चलते पतिराम यादव की बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बीसूराम के खिलाफ धारा 302 के तहत 10 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में करीब 11 माह चली सुनवाई के बाद आजीवन कारावास व 500 रूपए का अर्थदंड लगाया है। दोषी को जब से गिरफ्तार किया गया है, तब से वह जेल में बंद है।

ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, आठ आरोपी गिरफ्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पेंड्रा जीपीएम पुलिस ने सट्टा एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की है। जिसमे पुलिस ने रैकेट के संचालक,एजेंट समेत चार गांव से पकड़ाए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।।आरोपियों से पुलिस ने लाखों रुपये के सट्टा पट्टी मिले रिकॉर्ड सहित मोबाइल और नगदी भी जप्त किया है। और गिरोह के मुखिया से तलाशी में मिले ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे ग्रांडएक्सचेंज और थंडरएक्सचेंज में संलिप्तता के साक्ष्य फिलहाल पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश में जुट गई है।।

वही पुलिस अधिकारियों को लगातार सूचना मिल रही थी कि मरवाही थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर नंबरी सट्टा खिलाने का कारोबार चल रहा है , पुलिस ने जानकारी को गंभीरता से लेते हुए पहले मामले की जानकारी जुटाई फिर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए लाखों के सट्टा पट्टी के रिकॉर्ड्स समेत, मोबाईल और नगद जप्त किया गया है।

पुलिस ने मरवाही थाना क्षेत्र में कल्याण और गोल्डन नंबरी सट्टा खिलाने वाले गिरोह के सक्रिय

होने की सूचना पर जिले की एसपी आईपीएस भावना गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए साइबर सेल जीपीएम और मरवाही पुलिस को पूरे गिरोह पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। एसडीओपी मरवाही और डीएसपी साइबर सेल दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन टीमें गठित कर सट्टा खाईवालों पर रेड किया गया था। जिस पर टीमों ने ग्राम भर्रीडाड, लोहारी और मरवाही के कुल 8 सट्टा खाईवालों को नंबरी सट्टा खिलाने के साक्ष्य के साथ पकड़ा है जिनसे जुड़े लिंक के आधार पर इन सभी सट्टा खिलाने वालों के सरगना मरवाही निवासी स्नेहिल गुप्ता और आयुष जायसवाल को भी पकड़ा गया है। वहीं आरोपी स्नेहिल ने बताया कि सभी आरोपी गोल्डन और कल्याण सट्टा खिलाने में सक्रिय हैं जिसकी राशि का कलेक्शन साप्ताहिक रूप से ऑनलाइन और कैश माध्यम से लेकर इनको वह कमीशन देता है।

रैकेट संचालक स्नेहिल गुप्ता द्वारा ग्रांडएक्सचेंज और थंडरएक्सचेंज नाम के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर क्रिकेट सट्टा खिलाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जिस आधार पर इनके मध्यप्रदेश के और अन्य स्थानों के लिंक की जानकारी निकालकर आगे कार्यवाही किये जाने की बात पुलिस अधिकारी ने कही है। वहीं पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किए आरोपी स्नेहिल गुप्ता उम्र 23 वर्ष बनिया मोहल्ला मरवाही मुख्य सरगना डेली नीड्स की दुकान भी है, आयुष जायसवाल उम्र 22 वर्ष पुरानी बस्ती मरवाही स्नेहिल का पार्टनर है हिसाब किताब देखता है।

संतोष राय उम्र 38 वर्ष ग्राम चिचगोहना मरवाही सट्टा खाईवाल एजेंट बस स्टैंड में पान दुकान, श्रवण प्रसाद गुप्ता उम्र 47 वर्ष ग्राम लोहारी मरवाही सट्टा खाईवाल एजेंट, मो हासिम अंसारी उम्र 61 वर्ष मस्जिद मोहल्ला मरवाही सट्टा खाईवाल एजेंट, अंकित राय पिता उम्र 30 वर्ष न्यू बस स्टैंड मरवाही सट्टा खाईवाल एजेंट, चुनित राय उम्र 37 वर्ष ग्राम भर्रीडाड मरवाही सट्टा खाईवाल एजेंट, विजय ताम्रकार उम्र 34 वर्ष पुरानी बस्ती मरवाही सट्टा खाईवाल एजेंट को कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है।

वहीं पुलिस ने आरोपियों से 8 मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर लाखों की सट्टा के लेन देन के रिकॉर्ड्स और नगद रुपए लगभग 20000 मिले हैं। आरोपियों के लगभग 15 खातों और मोबाइल से मिले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के आधार पर और आरोपियों को पकड़ा जा है।

बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्या मामले में टीआई निलंबित

सरगुजा। जिले के सीतापुर के बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निरीक्षक प्रदीप जॉन लकड़ा को निलंबित कर दिया है। बता दें कि पुलिस पर हत्याकांड की लीपापोती का आरोप है। इस मामले में 10 दिन पहले ही टीआई निरीक्षक प्रदीप को आईजी ने लाइन अटैच किया था। संदीप मर्डर केस में अब तक निरीक्षक सहित सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को चुकी है। आईजी के निर्देश पर विभागीय जांच तेज हो गई है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। संदीप की पत्नी शालीमा राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगा चुकी है। न्याय नहीं मिलने पर दो बच्चों के साथ आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। बता दें कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलजोरा में रहने वाले मृतक आदिवासी युवक संदीप लकड़ा तीन महीना से लापता था। परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज की थी। आदिवासी समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद मामला दर्ज किया गया था। लगभग तीन महीने बाद संदीप लकड़ा के शव को मैनपाट के ग्राम लुरैना में पानी टंकी के नीचे बरामद किया गया था।

संक्षिप्त समाचार

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पाटिल व मुख्यमंत्री साय

राजनांदगांव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को बरगा में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय के अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और प्रभारी मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद संतोष पाण्डेय, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, जनपद अध्यक्ष प्रतिक्षा सूर्यकांत भंडारी, सभापति जिला पंचायत अशोक देवांगन, समाजसेवी रमेश पटेल, सरपंच बरगा कुमार सोनवानी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास तथा विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की कर रहे हैं समीक्षा.,राजस्व विभाग की योजनाओं और विभागीय गतिविधियों की ले रहे हैं जानकारी,.राजस्व विभाग द्वारा नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने डिजिटल नवाचारों पर चर्चा हो रही है . मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्व एवं खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, राजस्व विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री राहुल भगत, आयुक्त भू अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं।

बृजमोहन अग्रवाल संसद की दो स्थाई समितियों में सदस्य मनोनीत

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की दो स्थाई समितियों में सदस्य मनोनीत किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। श्री अग्रवाल पहले ही लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण प्राक्कलन समिति के सदस्य बनाए जा चुके हैं। ऐसे में श्री अग्रवाल को सदन की तीन अहम कमेटियों में लिया जाना यह बताता है कि उनके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। जारी आदेश के अनुसार बृजमोहन अग्रवाल को कैमिकल्स एवं फर्टिलाइजर कमेटी तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थाई समिति में सदस्य मनोनित किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह स्थाई समितियां संसद के अंदर ही गठित की गई ऐसी समितियां होती हैं जो किसी विशेष विषय या मंत्रालय से संबंधित मामलों पर गहराई से अध्ययन करती हैं। ये समितियां सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों का विस्तृत अध्ययन करती हैं और उनमें सुधार के लिए सुझाव देती हैं। किसी मुद्दे पर या विधेयकों पर पक्ष और विपक्ष में होने वाले गतिरोध को दूर करने के लिए भी संसद की स्थायी समिति अपनी भूमिका अदा करती है। उक्त समितियों के अलावा श्री अग्रवाल जिस प्राक्लन समिति में सदस्य हैं उसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है, जो व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में हैं। समिति प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव भी देता है।

कोरबा में डेंगू के रोकथाम के लिए उठाएं प्रभावी कदम : लखन लाल देवांगन

रायपुर। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा नगर और पूरे जिले में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री देवांगन ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र कोरबा सहित पूरे जिले के लोगों में डेंगू बीमारी से ग्रसित होने की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की जानकारी आम जनमानस से मिल रही है। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पोड़ी-उपरोड़ा, पाली और करतला क्षेत्र के साथ-साथ कोरबा शहरी क्षेत्र में भी लोग डेंगू बीमारी की चपेट में आ रहें हैं। इसकी रोकथाम के लिए नियमित तौर पर कीटनाशक का छिड़काव, नालियों व जल-जमाव के सफाई, आवश्यक चिकित्सकीय उपचार, दवाईयों के वितरण की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानी वितरण की व्यवस्था भी करना जरूरी है।

अग्रवाल समाज का सर्व समाज के लिए विशाल डायग्नोसिस कैंप अग्रोहा धाम में

रायपुर। अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रसेन जयंती के अवसर पर सर्व समाज के लिए 29 सितंबर को अग्रोहा धाम विशाल डायग्नोसिस कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें अग्रवाल समाज से जुड़े सभी डॉक्टर निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे। शिविर दोपहर को 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हैं। उक्त जानकारी अग्रवाल समाज के सलाहकार कैलाश मुरारका व प्रचार प्रसार मंत्री ज्योति अग्रवाल ने दी। मुरारका ने बताया कि डॉक्टर प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर कमलेश्वर अग्रवाल द्वारा तीन अक्टूबर को पूरे प्रदेश में अग्रसेन जयंती मनाया जाएगा। इससे पूर्व सभी मोहल्ला समितियों में अलग-अलग अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 29 सितंबर को अग्रवाल समाज के द्वारा विशाल डायग्नोसिस कैंप का आयोजन किया है जिसका लाभ रापुरियंस ले सकते है।

राहुल गांधी की तरह दीपक बैज की छत्तीसगढ़ में 'न्याय यात्रा'

बाबा और महंत के साथ शुरुआत संत गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि से

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से कांग्रेस की 6 दिवसीय न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। न्याय यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बैज कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत उन्होंने संत गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि गिरौदपुरी से की। यात्रा शुरू करने से पूर्व बैज शिवरीनारायण धाम भी पहुंचे और सोनाखान जाकर शहीद वीरनारायण सिंह को नमन भी किया।

प्रभु और पुरखों को याद करने के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बैज ने आशीर्वाद लिया, कार्यकर्ताओं को जोहार किया, स्नेह किया, प्यार किया, स्वागत-सत्कार किया। ढोल-नगाड़े, गाजे-बाजे के बीच बैज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ। चरण दास महंत, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, मोहन मरकाम सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोली के साथ बाबा गुरुघासी दास की तपोस्थली पहुँचे। बाबा को प्रणाम किया और छत्तीसगढ़वासियों की न्याय के लिए 'मनखे-मनखे एक बरोबर' का संदेश देते हुए यात्रा पर निकल पड़े।

बैज की न्याय यात्रा का यह पहला चरण है। इस पहले चरण में वे बलौदाबाजार के गिरौदपुरी से रायपुर तक करीब 130 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 6 दिवसीय यात्रा का समापन राजधानी रायपुर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर होगा। हर दिन यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और कांग्रेस की एकजुटता का संदेश देंगे। जैसे यात्रा के पहले दिन पार्टी के नेताओं ने दी है।

बैज की यह यात्रा एक तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तरह ही है। राहुल गांधी ने भी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। अब ठीक उसी अंदाज में पूरे

ताम-झाम, लाव-लश्कर, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ के साथ दीपक बैज छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा कर रहे हैं।

दीपक बैज की यह यात्रा कई मायनों में खास है। और उनके लिए अग्निपथ की तरह है। वो इस लिहाज से क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते छत्तीसगढ़ में दो महत्वपूर्ण चुनाव हुए और दोनों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहला चुनाव विधानसभा और दूसरा चुनाव लोकसभा का था। इन दोनों ही चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में कई लोग पार्टी में व्यापक बदलाव के नारे के साथ उठ खड़े हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा बैज पर कायम रहा। बैज ने अपने अध्क्षीय कार्यकाल का एक साल पूरा किया और आगे बड़ी चुनौतियों के साथ दूसरे कार्यकाल की ओर बड़ चले हैं।

कहते हैं कि पदयात्रा से नेताओं को बड़ी ऊर्जा और ताकत मिलती है। यात्रा हमेशा से ही भविष्य के लिए कारगर साबित होती रही है। इसके कई उदाहरण अतीत में हुए तमाम राजनीतिक और सामाजिक यात्राओं से मिलते हैं। दीपक बैज के लिए तो राहुल गांधी की यात्रा ही सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पदयात्रा से निकलने वाले परिणाम को बैज बेहतर समझते होंगे।

यही वजह ही कि बैज ने बिना देर किए ही सही मौके पर अपने पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। बैज के लिए सही अवसर दो तरह से है। पहला अवसर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बाद एक हो रही बड़ी घटनाओं ने कांग्रेस को सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा प्रदेशव्यापी मुद्दा दे दिया है। इसमें बलौदाबाजार में कलेक्टर-एसपी कार्याकाल आगजनी और कवर्धा के लोहारीडीह कांड सबसे बड़ा है। जिसे सदन से लेकर सड़क तक भुनाने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही दूसरा अवसर आगामी महीनों में छत्तीसगढ़ में होने वाला निकाय और पंचायत चुनाव है। बैज निश्चित ही इन अवसरों को पार्टी की सफलता में बदलना चाहते हैं। और यह बताना चाहते हैं कि वे चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन चुनौतियों का सामना तो बैज को अंदर भी करना पड़ रहा और बाहर भी। साथ और समर्थन पार्टी और जनता से कितना मिल पाया यह तो 2 अक्टूबर समापन के साथ पता चलेगा। फिलहाल तो बैज युवा जोश लिए अग्निपथ पर चल पड़े हैं।

नितिन ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा- जनता को अन्याय का दें हिसाब

रायपुर। कांग्रेस की न्याय पदयात्रा की आज बलौदाबाजार से शुरुआत हुई। पदयात्रा पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, उसके लिए पछतावा होना चाहिए। इस यात्रा में उन्हें अन्याय का हिसाब देना चाहिए।

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एससी वर्ग के छात्रों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, पीएससी के घोटाले में पूरी सरकार इंवॉल्व थी। लोग भूले नहीं है कि किस तरह से गरीबों को आवास से वांछित रखा गया, क्योंकि उनके चेहरे नहीं चमक रहे थे। पिछली सरकार शराब घोटाले में संलिप्त रही।

उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर महादेव सट्टा एप बनाया, जिसमें तत्कालीन सरकार के मुखिया इंवॉल्व थे। पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन का बाजार बना रखा था। इसके अलावा वहीं झारखंड मुख्यमंत्री के करीबी पर दर्ज एफ़आईआर पर उन्होंने कहा कि गुरुजी शिष्य को समझाने गए थे। अब गुरुजी जेल के रास्ते में है, तो शिष्य भी जेल के रास्ते में जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का खुला पिटारा

रायपुर। सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। प्रदेश में अब तक लगभग आठ विभागों में तीन हजार 474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों और आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।

छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाने में नहीं होगा भेदभाव : साव

नगर निगम, नगर पालिका के कामों की डिप्टी सीएम ने की समीक्षा

रायपुर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 2 दिनों तक नगरीय निकायों के कामों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक को लेकर अरुण साव ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाने के लिए जो भी कार्यों की स्वीकृति हुई उसकी समीक्षा की जा रही है। सरकार चाहती है कि विकास के कामों में कोई देरी नहीं हो। बिना किसी भेदभाव के हम विकास कार्यों के लिए नगर निगम और नगर पालिका को विकास की राशि मुहैया कराएं। हमारी कोशिश है कि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आने वाले वक्त में हमारी कोशिश है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में हमेशा आगे रहे। हमारी कोशिश है कि लोगों को नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ पीने का साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। डिप्टी सीएम ने कहा कि विकास

के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसी भी तरह का भेदभाव जनता के साथ नहीं होगा ये विश्वास दिलाते हैं।

अरुण साव ने कहा 2 दिनों में नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक हुई है। कल हमने नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा की थी। आज हमने राज्य के सभी पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। निकायों में जो विकास कार्य स्वीकृत हुए थे उनकी समीक्षा की। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हमने बिना किसी भेदभाव के राशि उपलब्ध कराई ताकि हमारे शहर सुसज्जित, स्वच्छ और सुंदर बनें। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और आज हमने इसकी समीक्षा की।

कांग्रेस भेदभाव का लगाती रही है आरोप- कांग्रेस पार्टी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि जहां जहां कांग्रेस नगर निगम और नगर पालिका में काबिज है वहां राशि खर्च करने के नाम पर भेदभाव सरकार की ओर से किया जा रहा है। बीते दिनों कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी विकास कार्यों में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया था। ज्योत्सना महंत ने कहा था कि आज भी कोरबा में जनता मदद के लिए मंत्री के पास नहीं बल्कि हमारे ज्यादा पहुंचते हैं।

शराब घोटाला : झारखंड सीएम के पूर्व सचिव पर एफआईआर

रायपुर। आबकारी घोटाले केस में झारखंड में रायपुर की ईओडब्ल्यू और एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। ये केस झारखंड के सीएम हेमंत के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और आबकारी के संयुक्त आयुक्त के खिलाफ दर्ज किया गया है। झारखंड में कथित शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी। रायपुर की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने अपनी प्राथमिकी में इसका जिक्र किया है। ईओडब्ल्यू ने अपनी प्राथमिकी में अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह सहित सात लोगों को आरोपित किया है।नीति में बदलाव करने के पीछे सुमित कंपनी को फायदा दिलाना बताया गया है। इससे करोड़ों रुपये का सरकार का नुकसान हुआ है। यही कंपनी छत्तीसगढ़ में भी शराब ठेके का काम कर रही थी। इन पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपितों में उत्पाद विभाग झारखंड के दो अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। आरोपितों में से कई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ रुपये के घोटाले में जेल में बंद हैं।ईओडब्ल्यू में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दिसंबर 2022 में झारखंड की शराब नीति में बदलाव किया गया था। इसकी बैठक रायपुर में अनवर ढेबर के ठिकाने में की गई थी। इस दौरान एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह सहित झारखंड के उत्पाद अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि झारखंड में भी छत्तीसगढ़ मॉडल पर मई 2022 से शराब की बिक्री हो रही थी। इनमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एपी त्रिपाठी को सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्यूरिटी लिमिटेड को शराब की बोतलों में होलोग्राम छापने का काम मिला था। इसी तरह मेसर्स सुमित फैसिलिटीस लिमिटेड को मैन पावर सप्लाई की जिम्मेदारी मिली थी। तीनों ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपित भी हैं। इनके विरुद्ध जांच के क्रम में झारखंड का कनेक्शन जुड़ा था। तीनों कंपनियों पर हुई कार्रवाई झारखंड में इन तीनों ही कंपनियों पर कार्रवाई हो चुकी है।

हाई कोर्ट की फटकार, मवेशियों को हटाने सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारी

बिलासपुर। सड़क हादसों में हो रही मवेशियों की मौत पर हाई कोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन हरकत आया है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अधिकारी आधी रात को अपने-अपने इलाके का दौरा कर सड़कों पर मिले मवेशियों को हटाया।

कोटा एसडीएम युगल किशोर उर्वाशा आधी रात को रतनपुर क्षेत्र के दौरे पर निकले। इस दौरान बिलासपुर-अम्बिकापुर नेशनल हाइवे पर बैठे आवारा मवेशियों को हटवाया। इसके साथ नेशनल हाइवे स्थित टोल गेट, पेट्रोल पंप, ढाबा संचालक समेत आसपास के रहवासियों की बैठक लेकर उनसे सड़क से मवेशियों को हटाने में मदद की अपील की।

इसके पहले कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के सभी एसडीएम की बैठक लेकर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि

मवेशियों के रोड पर बैठने के कारण यातायात बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दिन के साथ-साथ रात्रि में भी गश्त लगाकर सड़क से मवेशियों को हटाने कहा था। इस दौरान उन्होंने विशेषकर हाइवे, मस्तुरी और सेन्दरी से गुजरने वाली सड़कों पर खास ध्यान देने को कहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर सड़कों के निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। सभी एसडीएम अपने-अपने इलाके में दौरा कर सड़कों का निरीक्षण किया। कलेक्टर के द्वारा गठित टीम में राजस्व, नगरीय निकाय, पुलिस और वेटनरी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। टीम के साथ काऊ कैचर भी होता है।

कोरोना काल से बंद ट्रेनों के रेलवे स्टापेज होंगे पुनः बहाल

बिलासपुर। ज्ञात हो कि कोरोना काल से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बंद किया गया था, जिसके कारण आम नागरिकों , विद्यार्थी, कर्मचारी , व्यापारी सहित हजारों यात्रियों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। केंद्रीय लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संबंधित क्षेत्र में दौरा कर रहे श्री तोखन साहू जी से आमजनों ने प्रमुखता से इसकी पुनः बहाली की मांग की थी। जनता की इच्छानुसार केंद्रीय राज्यमंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर ट्रेन स्टॉपेज की पुनः बहाली की मांग रखी। जिसे रेल मंत्री ने सहजता से स्वीकार कर रेलयात्रियों के हित में निर्णय लिया। ट्रेन ठहराव की सूचना मिलते ही संसदीय क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। इस दिशा में अथक प्रयास के लिए जनता द्वारा केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू को? भारी मात्रा में फोन-संदेशों के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित किया गया।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

संशोधित
-:: द्वितीय सीमित निविदा सूचना पत्र ::-

क्रमांक/आब./निविदा/2024-25/1605 उ.ब. कांकेर, दिनांक 19/09/2024

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, उ.ब. कांकेर द्वारा जिला कांकेर में संचालित 04 देशी एवं 08 विदेशी मदिरा दुकानों में स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरा/एन.व्ही.आर तथा उससे संबंधित उपकरणों के अनुरक्षण एवं सुधार कार्य तथा रख-रखाव हेतु इस कार्यालय के निविदा क्रमांक/आब./निविदा/2024-25/1596 उ.ब. कांकेर, दिनांक 18.09.2024 से द्वितीय सीमित निविदा सूचना पत्र जारी किया गया है।

उक्त सूचना पत्र के पैराग्राफ 2 में वर्णित अतः उक्त अवधि के लिये को दिनांक 04.10.2024 से 03.10. 2025 तक पढ़ा जावे।

जी-242502776/4

जिला आबकारी अधिकारी
उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

तालाबंदी : 'मोदी की गारंटी' लागू करवाने हड़ताल पर बैठे अधिकारी-कर्मचारी

रायपुर। 'मोदी की गारंटी' लागू करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी राज्यव्यापी कलम बंद, काम बंद, ताला बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सरकारी कार्यालय में आज कामकाज बंद है। इसके साथ ही बूढ़ा तालाब स्थल इंडोर स्टेडियम परिसर में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्यालय बंद करने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने प्रदेश सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने की मांग करते हुए कहा कि फेडरेशन लंबे समय से शासकीय

सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता, अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने की मांग करता रहा है।

उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है। आज एक दिवसीय छुट्टी लेकर हड़ताल कर रहे हैं, आज के बाद अगर मांग नहीं मानी जाती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पूरे प्रदेश भर में कार्यालयों का बहिष्कार कर दिया जाएगा।

कमल वर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के आंदोलन में छह अगस्त को मुख्य सचिव ज्ञापन सौंपा गया था। 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच दूसरे चरण के लिए विधायकों, सांसदों व मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। इसी तरह तीसरे चरण में 11 सितंबर को जिला ब्लॉक में मशाल रैली निकालकर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया था।

उन्होंने कहा कि आज कार्यालयों का बहिष्कार कर हड़ताल कर रहे हैं। फेडरेशन के इस कलमबंद काम बंद हड़ताल को 112 मान्यता एवं गैर मान्यताप्राप्त संगठनों का समर्थन मिला है। कार्यालय बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद सभी कार्यालय बंद हैं।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर

(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
Main Portal: https: // eproc.egstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	158786 प्रथम आमंत्रण 18.09.2024	जिला जशपुर के एन.एच. 43 खडसा से कोमडो तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.94 कि.मी. निर्माण कार्य।	227.88
2	158789 प्रथम आमंत्रण 18.09.2024	जिला जशपुर के विकासखण्ड कांसाबेल के कोरंगा-बस्ती से गयारटोली पहुंच मार्ग लंबाई 2.20 कि.मी. निर्माण कार्य।	249.71
3	158745 प्रथम आमंत्रण 18.09.2024	1)जिला जशपुर के बेलसोंगा से रनपुर पहुंच मार्ग लंबाई 1.38 कि. मी. निर्माण कार्य। 2) जिला जशपुर के बहराखैर से जुड्वाईन पहुंच मार्ग लंबाई 1.63 कि.मी. निर्माण कार्य।	370.26
4	158747 प्रथम आमंत्रण 18.09.2024	जिला जशपुर के सन्ना मार्ग से केराकोना (केराकोना-बैगाटोला) मार्ग पर ईब नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	522.21
5	158792 प्रथम आमंत्रण 18.09.2024	जिला सूरजपुर के श्रीराम वन गमन पथ के मिसिंग लिंक मार्ग रक्सगंडा जलप्रपात पहुंच मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. निर्माण कार्य।	251.62
6	158832 द्वितीय आमंत्रण 19.09.2024	राज्य कर (वाणिज्य) रायपुर संभाग कं-1 सिविल लाईन रायपुर के मीटिंग हॉल के ऊपर अतिरिक्त कक्षों का निर्माण (द्वितीय एवं तृतीय तल में ऑफिस हॉल एवं रूम्स) कार्य विद्युतीकरण सहित । संभाग कं- 1 रायपुर।	249.73

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क. 03 से सं.क. 04 दिनांक 14.10.2024, सं.क. 06 दिनांक 07.10.2024 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 11.10.2024 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

जी-242502772/9

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

बार-बार चुनाव के चक्र से निकले देश

अवधेश कुमार

एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी उस दिशा में आगे बढ़ने के मोदी सरकार के निश्चय का संदेश है। हालांकि विरोधियों की प्रतिक्रियाएं वैसी ही हैं, जैसी पहले दिन से रही हैं। इस 8 सदस्यीय समिति ने सारे प्रासंगिक सवालों पर विचार कर उनके उत्तर तलाशने की अधिकतम संभव कोशिश की है। समिति को मुख्यत: सात कार्य दिए गए थे। जिनमें संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। त्रिशंकु सदन, दलबदल या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण बनने वाले गतिरोध का समाधान तलाशना। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। अगर साथ चुनाव संभव न हों तो इसके अलग-अलग चरणों और समयसीमा का सुझाव देना। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र न टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना। चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मानवबल सहित अन्य जरूरत का आकलन करना। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचानपत्र बनाए जाने की सिफारिश करना। साफ है कि जितने प्रश्न पहले उठ रहे थे या आज उठाए जा रहे हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए समिति को दायित्व सौंपा गया था और सबका व्यावहारिक समाधान इस रिपोर्ट में निहित है। समिति का सुझाव है कि पहले चरण में आठ राज्यों के चुनावों को एक साथ लाकर लोकसभा के साथ आयोजित किया जाए और उसके 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव हों। समिति के मुताबिक तीन चरणों के प्रयासों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। यानी उस समय से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने शुरू हो सकते हैं। समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के पहले कई देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया। ये देश हैं, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नैशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ मतदान होता है। स्वीडन में आनुपातिक चुनाव प्रणाली के तहत संसद (रिक्सडैग), काउंटी और नगर परिषदों के चुनाव एक ही समय में होते हैं। ये चुनाव हर साल सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं जबकि हर 5 साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को नगरपालिका व विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इंडोनेशिया में भी 2019 से एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। जो कुछ अन्य देश कर सकते हैं वह हम क्यों नहीं कर सकते? 1999 में ही विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने की बात कही गई थी। उसके बाद 2015 में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय मामलों की संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की। अगस्त, 2018 में फिर विधि आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें दो चरणों में चुनाव कराने का सुझाव था। विधि आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाए-घटाए जा सकते हैं तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे वांछित समय पर भंग किया जा सकता है। आजादी के बाद से 1967 तक सभी चुनाव निश्चित समयावधि में साथ ही होते थे। 1967 में कांग्रेस का एकाधिकार टूटने, आठ राज्यों में गठबंधन सरकारें बनने और उनके असमय गिर जाने या गिराए जाने से समस्या बढ़ी। कांग्रेस में नेतृत्व की आंतरिक लड़ाई के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौथी लोकसभा को समय पूर्व 1970 में ही भंग कर दिया। 1975 में आपातकाल लगाने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार ढाई साल बाद ही गिर गई। 1989 से 1999 का दशक भारतीय राजनीति में बड़े अस्थिरता का था जिसमें केंद्र और राज्यों की सरकारें असमय जाती रहीं। कुल मिलाकर, असामान्य स्थिति के कारण पूरा चुनावी चक्र गड्डु-मड्डु हो गया।

शक्तिशाली देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर

प्रह्लाद सबनानी

आस्ट्रेलिया के एक संस्थान, लोवी इन्स्टिटयूट थिंक टैंक, ने हाल ही में एशिया में शक्तिशाली देशों की एक सूची जारी की है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 नामक इस सूची में भारत को एशिया में तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बताया गया है। वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। इस इंडेक्स में अब केवल अमेरिका एवं चीन ही भारत से आगे है। रूस तो पहिले से ही इस इंडेक्स में भारत से पीछे हो चुका है। इस प्रकार अब भारत की शक्ति का आभास वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाने लगा है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2023 के इंडेक्स में भारत को 36.3 अंक प्राप्त हुए थे जो वर्ष 2024 के इंडेक्स में 2.8 अंक से बढ़कर 39.1 अंकों पर पहुंच गए हैं एवं भारत इस इंडेक्स में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है।

एशिया पावर इंडेक्स 2024 को विकसित करने के लिए कुल 27 देशों और क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का आंकलन एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। एशिया में जो नए शक्ति समीकरण बन रहे हैं उनका ध्यान भी इस इंडेक्स में रखा गया है तथा विभिन्न मापदंडों पर आधारित पिछले 6 वर्षों के आकड़ों का विश्लेषण कर यह इंडेक्स बनाया गया है। आर्थिक क्षमता, सैन्य (मिलिटरी) क्षमता, अर्थव्यवस्था में लचीलापन, भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता, कूटनीतिक, राजनयिक एवं आर्थिक सम्बंध एवं सांस्कृतिक प्रभाव जैसे मापदंडो पर उक्त 27 देशों एवं क्षेत्रों का आंकलन कर विभिन्न देशों को इस इंडेक्स में स्थान प्रदान किया गया है।

उक्त इंडेक्स में अमेरिका, 81.7 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। चीन 72.7 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर है। भारत ने इस इंडेक्स में 39.1 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जापान को 38.9 अंक, आस्ट्रेलिया को 31.9 अंक एवं रूस को 31.1 अंक प्राप्त हुए हैं एवं इन देशों का क्रमश: चतुर्थ, पांचवा एवं छठवां स्थान रहा है। इस इंडेक्स में प्रथम 5 स्थानों में से 4 स्थानों पर क्वाड के सदस्य देश हैं - अमेरिका, भारत, जापान एवं आस्ट्रेलिया। एशिया में अमेरिका की लगातार बढ़ती मजबूत ताकत के चलते उसे इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि, चीन की मजबूत

मिलिटरी ताकत के चलते उसे इस इंडेक्स में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जापान के इस इंडेक्स में तीसरे से चौथे स्थान पर आने के कारणों में मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति में लगातार आ रही गिरावट है। भारत ने चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। आर्थिक क्षमता एवं भविष्य में संसाधनो की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक, राजनयिक एवं आर्थिक सम्बंध के क्षेत्र एवं सांस्कृतिक प्रभाव के क्षेत्र में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब केवल अमेरिका और चीन ही भारत से आगे हैं एवं जापान, आस्ट्रेलिया एवं रूस भारत से पीछे हो गए हैं। जबकि, कुछ वर्ष पूर्व तक विश्व की महान शक्तियों में भारत का कहीं भी स्थान नजर नहीं आता था। केवल अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों को ही विश्व में महाशक्ति के रूप में गिना जाता था। अब इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

उक्त इंडेक्स तैयार करते समय आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि अन्य शक्तिशाली देशों का भी आंकलन किया गया है। साथ ही, विश्व में तेजी से बदल रहे शक्ति के नए समीकरणों का भी व्यापक आंकलन किया गया है। इस आंकलन के अनुसार अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना हुआ है। चीन तेजी से आगे बढ़कर दूसरे स्थान पर आया है। तेजी से बढ़ती सेना एवं आर्थिक तरक्की चीन की मुख्य ताकत है। उक्त प्रतिवेदन में यह तथ्य भी बताया गया है कि उभरते हुए भारत से अपेक्षाओं एवं वास्तविकताओं में अंतर दिखाई दे रहा है। इस प्रतिवेदन के अनुसार, भारत के पास अपने पूर्वी देशों को प्रभावित करने की सीमित क्षमता है। परंतु, वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। भारत अपने पड़ौसी देशों नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यांमार एवं अफगानिस्तान, आदि की विपरीत परिस्थितियों के बीच भारी मदद करता रहा है। आसियान के सदस्य देशों की भी भारत समय समय पर मदद करता रहा है, एवं इन देशों का भारत पर अपार विश्वास रहा है। कोरोना के खंडकाल में एवं श्रीलंका, म्यांमार तथा अफगानिस्तान में आए सामाजिक संघर्ष के बीच भारत ने इन देशों की मानवीय आधार पर भरपूर आर्थिक सहायता की थी एवं इन्हें अमेरिकी डॉलर में लाइन आफ क्रेडिट की सुविधा भी प्रदान की थी ताकि इनके विदेशी व्यापार को विपरीत रूप से प्रभावित होने से बचाया जा सके। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार भारत के पास भारी मात्रा में संसाधन मौजूद हैं एवं जिसके बलबूते पर आगे आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। साथ ही, भारत अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने की भी क्षमता रखता है। भारत ने हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। जिसके चलते लगातार तेज हो रहे आर्थिक विकास के बीच सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति और बेहतर हो रही है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मान्यता बढ़ रही है। साथ ही, बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत की सक्रिय भागीदारी बढ़ती जा रही है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एशिया के कई देशों के साथ अपने सम्बंधों को मजबूत किया है। अब तो अफ्रीकी देशों का भी भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है एवं भारत में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। भारत में हाल ही में अपनी कूटनीतिक एवं राजनयिक क्षमता में भी भरपूर सुधार किया है एवं इसके बल पर वैश्विक स्तर पर न केवल विकसित देशों बल्कि विकासशील देशों को भी प्रभावित करने में सफल रहा है। यूक्रेन एवं रूस युद्ध के समय केवल भारत ही दोनों देशों के साथ चर्चा कर पाता है एवं युद्ध को समाप्त करने का आग्रह दोनों देशों को कर पाता है। इसी प्रकार, इजराईल एवं हमास युद्ध के समय भी भारत दोनों देशों के साथ युद्ध समाप्त करने की चर्चा करने में अपने आप को सहज एवं सक्षम पाता है। आपस में युद्ध करने वाले दोनों देश भारत की सलाह को गम्भीरता से सुनते नजर आते हैं। भारत ने कभी भी विभिन्न देशों के आंतरिक स्थितियों पर अपनी विपरीत राय व्यक्त नहीं की है और न ही कभी उनके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप किया है। इस दृष्टि से वैश्विक पटल पर भारत की यह विशिष्ट पहचान एवं स्थिति है।

दक्षिण एशिया के देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है इसलिए भारत का पूरा ध्यान इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम कर अपने प्रभाव को बढ़ाना है। इसी मुख्य कारण से शायद भारत दक्षिण एशिया के देशों पर अधिक ध्यान देता दिखाई दे रहा है। जिसका आशय उक्त प्रतिवेदन में यह लिया गया है कि विश्व के अन्य देशों को सहायता करने की भारत की क्षमता तो अधिक है परंतु अभी उसका उपयोग भारत नहीं कर पा रहा है। हिंद महासागर पर भारत का ध्यान अधिक है और क्वाड के सदस्य देश मिलकर भारत की इस दृष्टि से सहायता भी कर रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों के अलावा विश्व के अन्य देशों की मदद करने के संदर्भ में भारत ने हालांकि अभी हाल ही के समय में बढ़त तो बनाई है परंतु अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत में आगे बढ़ने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं।

उक्त प्रतिवेदन में भारत को एशिया को तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बताया गया है परंतु वस्तुत: भारत अब एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बन गया है क्योंकि इस सूची में एशिया के बाहर से अमेरिका को भी एशिया में पहिले स्थान पर बताया गया है। एक अन्य अमेरिकी थिंक टैंक का आंकलन है कि भारत यदि इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो इस शताब्दी के अंत तक भारत, चीन एवं अमेरिका को भी पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली देश बन जाएगा।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रमाण-संग्रहाध्यायः (दूसरा अध्याय)

गतांक से आगे...

(67) अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुत: । पश्चाद्भारतमाख्यानं चक्रे तदुपवृ हितम्।।

(श्रादिपर्व अनुक्रमणिका) अर्थात् सत्यवती के पुत्र श्री व्यासजी ने अष्टादश पुराणों का संकलन करने के बाद पुराणों का उपवृ हण रूप महाभारत ग्रन्थ बनाया।

(68) लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवा: सौति: पौराणिक:। (आदिपर्व 1।11) था। अर्थात् - सूतपुत्र लोमहर्षण का आत्मज उग्रश्रवा पुराणों का ज्ञाता

(69) पुराणसंश्रिता: पुण्या: कथा धर्मार्थसंश्रिता:। (आदिपर्व 1।16) अर्थात् - पुराणों की पवित्र कथाएँ धर्म और अर्थ की देने वाली हैं।

(70) पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना प्रकाशिता। (आदिपर्व 1।86) अर्थात् - पुराणरूप पूर्ण चन्द्रमा से वेद रूप चांदनी छिटकती है ।

(71) इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबू हयेत्। (आदिपर्व 1।64) अर्थात् - इतिहास और पुराणों द्वारा वेदों को प्रवृद्ध करना चाहिए । महाभारत ग्रन्थ आर्यजाति का विश्वकोश कहा जाता है। उक्त ग्रन्थ के उपर्युक्त प्रमाणों में कितने सौष्ठव के साथ पुराणों को स्मरण किया गया है यह दर्शनीय है।

वाल्मीकीय-रामायणा- (72) एतच्छ्रुत्वा रह: सूतो राजानमिदमब्रवीत् । श्रूयतां यत्पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम् ।। (बालकाण्ड 6।1)

अर्थात् - [सन्तान के अभाव से दु:खित हुये दशरथ जी के प्रति सुमन्त्र मन्त्री ने] राजा के ऐसे वचनों को सुनकर एकान्त में कहा कि महाराज ! मैंने आपके सम्बन्ध में पुराण ग्रन्थों में जो कुछ सुन रक्खा है वह श्रवण कीजिए ।

(73) इत्युक्त्वान्त:पुरद्वारमाजगाम पुराणवित् ।। (अयोध्या 15।18)

अर्थात् - पुराणों के ज्ञाता सुमन्त्र लोगों को समझाकर अन्त:पुर के द्वार पर पहुंचे । **(क्रमश:)**

विश्व रेबीज दिवस

रौनक

रेबीज़ बीमारी का नाम सुनते ही हमारे मन में डर पैदा हो जाता है और डर होना लाजमी भी है क्योंकि अगर रेबीज का सही समय पर इलाज ना किया जाये तो इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। सही समय पर इस बीमारी का पता चलना बेहद जरूरी हैं। हर साल 28 सितम्बर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। इस दिन इस बिमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को बताया जाता हैं।

इसके साथ ही इस दिन को चुनने की एक वजह यह भी है कि आज ही के दिन विख्यात फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। लुईस

पाश्चर ही वह व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार रेबीज की वैक्सीन का आविष्कार कर मेडिकल जगत को एक बेहद अमूल्य तोहफा दिया था।लुईस पाश्चर और उनकी टीम ने ही 1885 में पहली बार रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन विकसित की थी। रेबीज बीमारी होने इसका कारण है लायसावायरस। ये वायरस शरीर में ये कुत्ते, बिल्ली और बंदर जैसे जानवरों के काटने से प्रवेश करता है और व्यक्ति को रेबीज़ से संक्रमित कर देता है।

सबसे पहले विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, 2007 को मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका और एलायंस फोर रेबीज कंट्रोल के बीच साझेदारी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया परन्तु दुनिया में इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत रेबीज के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित होने के बाद की गई थी और अब इस दिवस का कॉर्डिनेशन ग्लोबल एलायंस फोर रेबीज कंट्रोल के द्वारा किया जाता है।

विश्व रेबीज़ दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन को मनाने का उदेश्य है रेबीज़ की बीमारी पर लोगों को जागरूक करना और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक वायरल बीमारी है जो कि जानवरों के द्वारा इंसानों में दिमाग की सूजन का कारण बनती है । यह दिन लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति सचेत करता है साथ ही जानवरों की बेहतर देखभाल और रेबीज जैसी प्रतिकूल सिचुएशन से निपटने की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक इस बीमारी की घटना को खत्म करना है। विश्वभर के स्वास्थ्य संगठनों ने इस दिन को रेबीज के टीकाकरण शिविरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लोगों से कहा है और इस बीमारी को रोकने के लिए लोगों की सामूहिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना है। इसके साथ ही यह दिन हेल्थ फर्म्स और वेट्रीनरी ग्रुप्स, क्विज, निबंध प्रतियोगिताओं और अन्य जागरूकता अभियानों के द्वारा और कैंपेन मैराथन के जरिए मनाया जाता है।

हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों की लिस्ट हो रही खाली

अभिनय आकाश

वेस्ट एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा हुआ देश इजरायल भूमध्य सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। बाकी तीन दिशाओं में अरब देश हैं। नार्थ में लेबनना और सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ में इजिप्ट है। इजरायल का जिक्र होता है तो इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी जिक्र आम है। सबसे सटीक या चकित करने वाला ऑपरेशन उसे माना जाता है जब किसी ऐसी चीज को हथियार बनाया जाए, जिसकी कल्पना भी मुश्किल हो। इस संदर्भ में इजरायली एजेंसी मोसाद के किस्से आम हैं। इजरायली एजेंसियों के कारनामे हमेशा चर्चा में रहते हैं। माइकल बेन जोहार और निसिम मिसाल ने अपनी किताब मोसाद में लिखा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्टेट को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ता है जो लोकतांत्रिक नहीं होता। ये सच है कि इसकी हदें अक्सर पता नहीं चलती। इसलिए आपको सबसे बेहतरीन लोगों को चुनना होता है। सबसे गंदे काम सबसे ईमानदार लोगों से कराए जाने चाहिए।

इजरायल एक साल से युद्ध लड़ रहा है। एक ओर हमास से उसकी लड़ाई जारी है तो दूसरी ओर हिजबुल्ला पर भी इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हाल ही में लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली थी। हिजबुल्ला अभी संभलता कि एक बार फिर इजरायल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके उसे पूरी तरह से बैकफुट पर कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को दूसरी चेतावनी भी जारी की, जिसमें उनसे खतरे से दूर रहने का आग्रह किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। जिस किसी के लिविंग रूम में मिसाइल और गैरेज में रॉकेट होगा, उसके पास घर नहीं होगा। इजरायल अपने सटीक हमले में हिजबुल्ला के टॉप

कमांडरों को भी निशाना बना रहा है। ताजा उदाहरण इब्राहिम कुबैसी का है। 24 सितंबर को इजरायल की तरफ से किए गए हमले में उसकी मौत हो गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इज़राइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है और उसके टॉप लीडर्स की सूची को खाली कर रहा है।

इब्राहिम कुबैसी- इजराइली सेना ने कहा है कि उसने बेरूत पर एक हमले में हिजबुल्ला की मिसाइल और रॉकेट इकाई के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इब्राहिम कोबेसी मारा गया तथा वह इजराइल की ओर मिसाइल और रॉकेट हमले करने के लिए जिम्मेदार था। इजराइली सेना ने कहा कि हमले के समय कोबेसी के साथ अन्य प्रमुख कमांडर भी थे, लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि इसमें क्या कोई अन्य मारा गया या घायल हुआ है। इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कुबैसी को हिज्बुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का प्रमुख बताया। आईडीएफ ने कहा पिछले कई सालों से और युद्ध के दौरान, वह इज़राइली होम फ्रंट पर लॉन्च के लिए ज़िम्मेदार था। उसे हिज्बुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व का करीबी भी बताया गया। इजराइल का दावा है कि कुबैसी 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया था और उसने बद्र क्षेत्रीय प्रभाग के प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया था। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि यह कुबैसी ही था जिसने 2000 में माउंट डोव में अपहरण हमले की योजना बनाई थी। इस ऑपरेशन में आईडीएफ के स्टाफ सार्जेंट बेन्यामिन अवराम, स्टाफ सार्जेंट आदि अवितान और स्टाफ सार्जेंट उमर सवैद की जान चली गई थी। वाईनेट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कुबैसी को हाल ही में हिज़्बुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह को सीधे रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था।

अली कराकी- आईडीएफ ने लेबनान पर हवाई हमले भी किए थे, अधिकारियों ने कहा कि यहूदी राष्ट्र हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी को निशाना बना रहा था। उन्हें हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य निकाय जिहाद परिषद का सदस्य भी कहा जाता है। एक लेबनानी अधिकारी ने स्काई न्यूज अरेबिया को बताया कि कराकी हमले में मारा गया, हिजबुल्लाह ने कहा कि हत्या का प्रयास विफल रहा और उसे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

इब्राहिम अकील- बीते हफ्ते लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी विस्फोटों के कुछ ही दिनों बाद, इज़राइल ने बेरूत में एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया और हिज़्बुल्लाह के दो शीर्ष सैन्य कमांडरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला। मारे गए लोगों में से एक इब्राहिम अकील था, जो हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स का एक टॉप लीडर भी था। आईडीएफ ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि इब्राहिम अकील के हाथों पर इजरायली, अमेरिकी, फ्रांसीसी, लेबनानी और कई अन्य निर्दोष लोगों का खून लगा था। आईडीएफ के अनुसार, 62 वर्षीय अकील ने फुआद शुक्र की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के सशस्त्र बलों के दूसरे-इन-कमांड के रूप में कार्यभार संभाला था। अकील 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया और समूह के भीतर एक छायादार व्यक्ति बना रहा, जिसने कोई सार्वजनिक उपस्थिति या बयान नहीं दिया। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हुए बम विस्फोटों में कथित भूमिका के लिए वह अमेरिका द्वारा वांछित था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरक पर हुए बम विस्फोटों में 241 अमेरिकी लोगों की जान चली गई थी।

फुआद शुक्र- हिजबुल्लाह ने 28 जुलाई को गोलान हाइट पर हमला किया था, जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई थी। इस पर इज़राइल ने उचित समझे जाने पर जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। बाद में 30 जुलाई को इजराइल ने शीर्ष सैन्य कमांडर फुआद शुक्र को निशाना बनाते हुए लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर दिया। अल-हज मोहसिन के नाम से भी जाने जाने वाले शुक्र 1982 में लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के दौरान हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह के दाहिने हाथ भी थे। अटलांटिक काउंसिल थिंक-टैंक के साथ हिजबुल्लाह के विशेषज्ञ निकोलस ब्लैनफोर्ड के अनुसार, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्र हिजबुल्लाह के हाई टेक हथियारों को प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार था, जिसमें सटीक-निर्देशित मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और यूएवी शामिल हैं। इज़राइल द्वारा वांछित होने के अलावा, शुक्र अमेरिका की तरफ से भी वांटेड घोषित था। उसने 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरकों पर बमबारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 241 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए थे।

इज़राइल ने यह भी दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के अन्य वरिष्ठ कमांडरों जैसे कि नस्र क्षेत्रीय डिवीजन के कमांडर तालेब अब्दुल्ला और अज़ीज़ क्षेत्रीय डिवीजन के कमांडर मोहम्मद नासिर को भी मार गिराया है। इसके अलावा, लेबनानी समूह के कुलीन राडवान फोर्स के उप प्रमुख विसम अल-ताविल को 8 जनवरी को दक्षिणी लेबनान में एक हमले में मार दिया गया, जिसके लिए इज़राइल को दोषी ठहराया गया।

आज का इतिहास

1929 सुर साम्राज्ञी महान पार्श्वगायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ।
1950 इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60 वां सदस्य बना।
1958 फ्रांस में संविधान लागू हुआ।
1963 वामा!, अब रॉय लिचेंस्टीन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है, लियो कैस्टेलि गैलरी, न्यू यॉर्क सिटी में आयोजित एक प्रदर्शनी में पहली फिल्म थी।
1972 पॉल हेन्डरसन ने सोवियत आइस हॉकी टीम के शिखर सम्मेलन श्रृंखला में कनाडा की जीत हासिल करने के साथ, व्लादिस्लावट्राइक के खिलाफ खेल-जीतने का लक्ष्य बनाया।
1978 पोप जॉन पॉल I की मृत्यु केवल 33 दिनों के बाद उनके पोप चुनाव के बाद एक स्पष्ट मायोकार्डिअल इन्फ्रक्शन के रूप में हुई, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में सबसे अधिक वर्ष तीन पॉप्स हुए।
1994 एतोमिया के जल पोत के तुर्क सागर में डूब जाने से 800 लोगों की मृत्यु हुई।
1994 तेलिन, एस्टोनिया और स्टॉकहोम, स्वीडन के बीच आवागमन करते हुए नौका एम एस एस्टोनिया डूब गई, जिसमें दावा किया गया कि बाल्टिक सागर में सबसे खराब दुर्घटनाओं में से एक में 852 लोग रहते हैं।
1995 रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने पूर्व यूगोस्लाविया में रूसी शांति बनाए रखने की पेशकश की है। यह नाटो बलों के साथ काम कर रहा होगा बशर्ते कि नाटो सर्ब बलों पर बमबारी करना बंद कर दे।
1995 बॉब डनार्ड की अगुवाई में 30 से अधिक भाड़े के लोग कोमोरोस इनान पर तख्तापलट के प्रयास में उतरे, 1975 के बाद से अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र पर उनका चौथा।
1996 अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने तालिबान द्वारा बर्बाद और हत्या कर दी।
2003 एक बिजली आउटेज ने इटली के देश के 90% के करीब ब्लैक आउट कर दिया है। बिजली कटौती से ट्रेनों और लिफ्ट में फंसे हजारों लोगों को छोड़ दिया गया।
2008 स्पेसएक्स फाल्कन 1 कक्षा बनाता है, ऐसा करने वाला पहला निजी तौर पर विकसित तरल-ईंधन वाला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान बन गया है।
2009 ईरान देश ने लंबी दूरी की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। यह देश के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर विवाद के बीच आता है। मिसाइलों के क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता है और जहां तक इजरायल में हैं।

चिकित्सक आंदोलन पर ममता की विरोध की प्रवृति उल्टी पड़ी

योगेंद्र योगी

संघीय ढांचे के तहत बने कानूनों और अदालतों के आदेशों के प्रति अडिय़ल रूख अपनाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरकार अपने ही लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के बाद चले आंदोलन से ममता के तेवर ढीले पड़ गए। ममता ने कल्पना भी नहीं की होगी पश्चिमी बंगाल में यह आंदोलन सरकार की चूलें हिला देगा। केंद्र सरकार और अदालतों के आदेशों के प्रति तीखे तेवर अपनाने वाली ममता इस्तीफा तक देने को तैयार हो गई। ममता के समझ में आ गया कि राजनीतिक द्वेषवश केंद्र सरकार की उपेक्षा की जा सकती है किन्तु प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए राज्य के लोगों की नाराजगी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ देश ही नहीं विदेशों में भी आंदोलन हुए। इस घृणित अपराध के विरोध में ममता सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ पश्चिमी बंगाल के हर वर्ग ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताली चिकित्सकों ने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को हटाया जाना और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के पद से हटाने की मांग की। ममता बनर्जी ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि वो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दुर्गा पूजा तक उनके पद पर बनाए रखेंगी। भारी विरोध के बाद आखिरकार गोयल का तबादला करना पड़ा। हड़ताली चिकित्सकों डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में उनके सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जाएं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार यह बताए कि 100 करोड़ रुपये का बजट किस प्रकार अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए %रेफरल सिस्टम % को सुधारने और भर्ती में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की भी बात कही। जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने और संस्थानों की नीतियों में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से उनकी आवाज़ को प्रमुखता दी जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। पश्चिमी बंगाल में अराजकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के बाद अराजकतत्वों ने अस्पताल पर हमला कर दिया। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ और मरीजों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। असामाजिक तत्वों ने अपराध के घटना स्थल पर तोडफ़ोड़ की और अपराध के सबूत मिटाने का प्रयास किया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज और पुलिस प्रशासन आरोपियों परोक्ष तौर पर आरोपियों के पक्ष में खड़ा नजर आया। दुष्कर्म और हत्या को आत्महत्या का मामला बता कर रफादफा करने का प्रयास किया गया। पुलिस और प्रशासन के पक्षपातपूण रवैये के बाद अदालत के आदेश से मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया। इसके बाद हर तरफ ममता सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद हुआ। भारी विरोध के बाद ममता को समझ में आ गया कि केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार की खिलाफत करने की तरह इस आंदोलन से नहीं निपटा जा सकता।

पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के प्रति विरोध और प्रदर्शन से सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी ने इसे अपना हथियार बना लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब ममता सरकार ने विरोध नहीं किया हो। इसी प्रवृति का परिणाम है कि महिला चिकित्सक की मौत से पनपे आंदोलन को दबाने-कुचलने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की ही

तरह ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर मामले में विरोध करती रहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे के मुद्दे पर ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ बातचीत में पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल नहीं किया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा। तीन पेज के लेटर में ममता ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे बिना इस तरह की एकतरफा बातचीत हमें मंजूर नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड जारी करने की मांग को लेकर राज्य विधानसभा परिसर में धरना दिया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के लोगों को योजनाओं से वंचित कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि आप कहते हैं कि बंगाल को पैसा मत दीजिए. तो फिर हमसे पैसे भी मत लीजिये। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में केंद्र ने जीएसटी के लिए बंगाल से 6,80,000 करोड़ रुपये लिये हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने आईपीएस राजीव कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि इस देश में कोई बिग बॉस नहीं है। यहां केवल जनता ही बिग बॉस है। केवल लोकतंत्र ही इस देश का बड़ा मालिक है। यह मेरी जीत नहीं है। यह संविधान की जीत है। यह भारत की जीत है। इसके बावजूद सत्ता के नशे में ममता चिकित्सकों के आंदोलन के मामले में अपना यह बयान भूल गई। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के प्रमुख राजीव कुमार पर सारदा और रोज वैली पोंजी योजनाओं में संभावित अभियुक्त होने का आरोप लगाया था। सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई के विरोध में धरना दिया और वहीं पर कैबिनेट की बैठक की और वहां पुलिस वीरता पुरस्कार भी दिए। उन्होंने अपने धरना को सत्याग्रह बताया। उन्होंने कहा कि वह देश और संविधान को बचाने के लिए धरने पर बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि कमिश्नर राजीव कुमार की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और न ही उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अदालत के गुणगान करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिकूल फैसला आने पर अदालतों के विरोध में भी पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को अवैध माना। उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली के दौरान ममता ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता न्यायपालिका और निर्णयों के एक हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों को रद्द करने का न्यायालय का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। उन्होंने दावा किया, मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं फैसले के बारे में बात कर रही हूं।

इसी तरह ओबीसी आरक्षण कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद ममता टिप्पणी करने से बाज नहीं आई। पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) आरक्षण कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस पर सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आईं। सीएम बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को ही तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार और अदालतों के आदेशों के प्रति पूर्वाग्रह का नजरिया रखने वाली पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विरोध की यह प्रवृत्ति चिकित्सकों के आंदोलन में काम नहीं आ सकी। मुख्यमंत्री ममता शायद भूल गई कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है। इससे निपटने के तौर-तरीके अलग हैं। यदि लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो जिस बूते केंद्र और अदालतों का विरोध किया जा रहा है, वह नींव खिसक जाएगी।

श्रीलंका में बदलाव ला पाएंगे दिसानायके?

शोभना जैन

भीषण आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, भारी जनअसंतोष और राजनैतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे श्रीलंका में इस सप्ताह हुए राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके की जीत एक बड़े बदलाव के रूप में देखी जा रही है। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में न केवल वामपंथी दल के राष्ट्रपति का चुना जाना एक बड़े बदलाव वाली खबर है, बल्कि अब सबकी नजर इस ओर है कि अपनी वामपंथी नीतियों से वह देश को इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाते हैं, देश में सभी को कैसे भरोसे में लेकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं और अगर विशेष तौर पर भारत की बात करें तो चीन

के प्रति झुकाव वाले अनुरा की पार्टी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाने के लिए कैसे संतुलन बनाती है। वैसे लगता तो यही है कि अनुरा देश को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए निजी तथा विदेशी निवेश भी लेंगे. चीन की तरफ झुकाव वाले अनुरा से उम्मीद की जा रही है कि वह भारत के साथ भी रिश्ते बनाने में व्यावाहरिक रास्ता अपनाएंगे. अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी उनके दल ने लिखा था कि श्रीलंका अपने भूभाग को भारत सहित क्षेत्र के किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बनने की इजाजत नहीं देगा। श्रीलंका पंरपरागत रूप से भारत का प्रगाढ़ मित्र रहा है। न केवल दोनों देश भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं बल्कि दोनों के बीच प्राचीनकाल से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों की जनता के बीच भावनात्मक रिश्ते हैं. हाल के आर्थिक संकट के दौरान भी भारत ने हर बार की तरह श्रीलंकाई जनता की सहायता की. सवाल है कि अनुरा सरकार इन चुनावी वादों पर अमल कैसे कर पाती है। श्रीलंका आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में है, ऐसे में निश्चित तौर पर वहां यह बदलाव श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और सरकार में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भरोसे को पैदा करने के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है। 55 साल के वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) गठबंधन के प्रमुख हैं। श्रीलंका की पूर्ववर्ती सरकारों के आर्थिक बदहाली से निपटने में नाकामयाब होने के बाद अनुरा में लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दिसानायके को महज 3 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में पहले राउंड में दिसानायके को 42.31त्न और उनके प्रतिद्वंद्वी रहे सजीथ प्रेमदासा को 32.76त्न वोट मिले। इस साल फरवरी महीने में अनुरा कुमारा दिसानायके जब भारत आए थे, तो किसी ने शायद ही सोचा था कि करीब सात महीने बाद वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे। श्रीलंका के इतिहास में ये पहली बार है जब चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी 50 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिले, जिसकी वजह से दूसरे राउंड की गिनती की गई।

संघवाद को नुकसान पहुंचाने वाला एक शब्द है 'उपकर'

डेरेक ओ ब्रायन

'द इंडियन एक्सप्रेस' में 16 जनवरी, 2012 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 'मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र पर दबावपूर्ण संघवाद की नीति अपनाने और इस प्रकार वित्तीय आबंटन की सभी शक्तियों पर एकाधिकार करके राज्यों को अधीनस्थ स्थिति में धकेलने का आरोप लगाया, यहां तक कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को भी कम किया।'

आपके स्तंभकार को स्पष्ट रूप से याद है कि तत्कालीन वित्त मंत्री, मिलनसार अरुण जेतली ने 2015 में किसी समय संसद में अपने कमरे में लगभग आधा दर्जन साथी सांसदों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। हमारे विनम्र मेजबान अच्छी खबर का जश्न मनाना चाहते थे। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को विभाज्य कर पूल का हस्तांतरण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। हम सभी ने इसे संघवाद की बड़ी जीत के रूप में देखा। लेकिन जेतली के बॉस, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के विचार कुछ और थे। संघवाद को नुकसान पहुंचाने वाला एक गंदा चार-अक्षर वाला शब्द : 'उपकर' (सैस) है।

जैसा कि वाणिज्य में कोई भी स्नातक आपको बताएगा कि उपकर विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है यानी, एकत्र किया गया धन राज्य सरकारों के साथ सांझा नहीं किया जाता है। उपकर एक विशिष्ट कर है जिसे केंद्र सरकार किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए धन जुटाने के लिए लगाती है। केंद्र सरकार वर्तमान में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर लगाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क और बुनियादी ढांचा, कृषि और विकास, स्वच्छ भारत, निर्यात और कच्चे तेल आदि पर उपकर है। इस पर विचार करें। 2012 में, 'उपकर' केंद्र सरकार के कुल कर राजस्व का 7 प्रतिशत था। 2015 में, यह बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया। 2023 में, उपकर ने कुल कर राजस्व का 16 प्रतिशत योगदान दिया। 2019-23 से, केंद्र सरकार ने उपकर के रूप में 13 लाख करोड़ रुपए

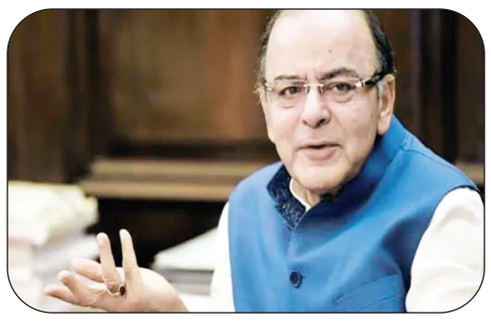

एकत्र किए हैं। इसमें जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर शामिल नहीं है। पिछले 5 वर्षों में इसने कच्चे तेल पर 'उपकर' के रूप में 84,000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में उपकर का हिस्सा 3 गुना बढ़ गया है, जो 2011 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 18 प्रतिशत हो गया है। उपकर और अधिभार में इस वृद्धि ने विपरीत रूप से करों के विभाज्य पूल में कमी ला दी है। विभाज्य पूल 2011 में सकल कर राजस्व के 89 प्रतिशत से घटकर 2021 में 79 प्रतिशत हो गया है। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों को कर हस्तांतरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने उजागर किया कि 2018-19 में, केंद्र सरकार ने भारत के समेकित कोष (सी.एफ.आई.) में विभिन्न उपकरों के माध्यम से एकत्र किए गए 2.75 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए रोक लिए। वर्ष के दौरान एकत्र किए गए सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर के 10,000 करोड़ रुपए 'न तो संबंधित आरक्षित निधि में स्थानांतरित किए गए और न ही उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए जिसके लिए उपकर एकत्र किया गया था'।

अधिक चिंताजनक बात यह है कि पिछले एक दशक में कच्चे तेल पर उपकर के रूप में एकत्र किए गए 1.24 लाख करोड़ रुपए 'निर्दिष्ट आरक्षित निधि (तेल उद्योग विकास बोर्ड) में स्थानांतरित नहीं किए गए और सी.एफ.आई. में ही रखे गए'। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आरक्षित निधियों का निर्माण न होना/संचालन न होना यह सुनिश्चित करना मुश्किल बनाता है कि उपकर और शुल्क संसद द्वारा इच्छित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए हैं। उपकर और अधिभार लगाने का मुख्य कारण केंद्र सरकार का अपना राजस्व बढ़ाना है। इसकी एक बड़ी आलोचना यह रही है कि उपकर बढ़ाने के बावजूद राजस्व में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई है। पिछले 10 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में मामूली वृद्धि हुई है, जो 2014 में जी.डी.पी. के 8.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में जी.डी.पी. के 9.6 प्रतिशत पर पहुंच गई हैं(एक प्रतिशत से भी कम)।

हाल ही में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एन.डी.ए. और विपक्ष शासित राज्यों के 8 अन्य मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की कि उच्च प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. वाले राज्यों को उनके आर्थिक प्रदर्शन के लिए अनुपातहीन रूप से कम कर आबंटन प्राप्त करके दंडित किया जा रहा है। 80 के दशक की शुरूआत में, सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि उपकर और अधिभार एक विशिष्ट उद्देश्य और सीमित समय अवधि के लिए लगाए जाने चाहिएं। 2010 में, पुंछी आयोग ने कहा कि उपकर और अधिभार का विस्तार वित्त आयोगों की सिफारिशों को कमजोर करने के बराबर है और राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व में उनके उचित हिस्से से वंचित करता है। इसमें आगे विस्तार से बताया गया है कि हम अनुशंसा करते हैं कि केंद्र सरकार को सकल कर राजस्व में उनके हिस्से को कम करने के उद्देश्य से सभी मौजूदा उपकरों और अधिभारों की समीक्षा करनी चाहिए।

सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया है। लगाए जाने वाले उपकरों की संख्या और मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। जो राज्य वैचारिक रूप से सत्तारूढ़ व्यवस्था का विरोध करते हैं, उन्हें अक्सर उनके उचित हक से वंचित किया जाता है। संसद के गलियारों में विपक्ष के अनुभवी सांसद वास्तविकता पर अफसोस जताते हैं।

राहुल को विदेश में बोलते समय सावधान रहना चाहिए

जूलियो रिबैरो

राहुल गांधी को कम से कम 2029 तक अमरीका या ब्रिटेन में बातचीत की व्यवस्था करने के सैम पित्रोदा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से बचना चाहिए, जब तक कि अगले लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल की नापसंदगी इतनी तीव्र और इतनी व्यक्तिगत है कि जब वे अपने भाषणों में मोदी का जिक्र करते हैं तो वे अपनी गलती मान लेते हैं। घर में राजनीतिक विरोधियों पर जहर उगलना ही काफी बुरा है। विदेश में ऐसा करना उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए कई विदेशी गण्यमान्य व्यक्ति नई दिल्ली आते हैं। कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलते हैं। इन गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने का कोई उदाहरण नहीं है। यह सही है कि हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करने के कई कारण हैं, खासकर उनके दोहरेपन के लिए, लेकिन ये लड़ाई भारत में भारतीयों को लडऩी है। विदेशियों को हमारी आंतरिक समस्याओं में नहीं उलझना चाहिए।

राहुल गांधी तेजी से नरेंद्र मोदी के लिए एक वास्तविक खतरा बनते जा रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें एक बड़ी छलांग दी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने सदन में अपनी उपस्थिति दोगुनी कर दी। भाजपा अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में हार गई। आश्चर्य की बात यह है कि मोदी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन करते समय शंकराचार्यों की भूमिका निभाने के बावजूद वह अयोध्या सीट भी हार गए। एक अधिक परिपक्व राजनेता अगली बार नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए उस छोटी जीत का लाभ उठाने की योजना बनाएगा। ऐसा लग रहा था कि राहुल ठीक यही कर रहे थे जब उन्होंने लोकसभा में सरकार की नीतियों पर हमलों का नेतृत्व किया। उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के एकमात्र उद्देश्य से फैलाई जा रही नफरत और विभाजनकारी भावना की ओर इशारा किया। और फिर वह संयुक्त राज्य अमरीका के लिए उड़ान भरते हैं और अपने मित्र और विश्वासपात्र सैम द्वारा लक्षित चुनिंदा दर्शकों को संबोधित करते हैं, शायद भ्रमित दर्शकों के सामने मोदी के खिलाफ बोलते हैं और ऐसा करके अपनी ही छवि खराब

करते हैं।

इसके विपरीत, नरेंद्र मोदी, एक शानदार राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में एकत्रित हुए भारतीयों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया और विदेश में खोई हुई जमीन वापस पा ली। भारत के विशाल और बढ़ते बाजारों की तलाश अमरीका और विभिन्न यूरोपीय शक्तियों द्वारा की जा रही है। सिर्फ इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेशों में बहुत मांग है। नरेंद्र मोदी एक चतुर और गणना करने वाले राजनीतिज्ञ हैं। वे एक बेहतरीन वक्ता हैं। न्यूयार्क में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्होंने पहले हमारे देश में न कहा हो। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इतने दृढ़ विश्वास और जोश के साथ कहा कि उन्होंने अपने श्रोताओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने शहर मुंबई में मैंने शिवसेना पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को कम से कम एक दर्जन मौकों पर बोलते सुना है। उन्होंने अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोदी भी ऐसा करते हैं। लेकिन मोदी अपने श्रोताओं का ध्यान आर्ज़षित करने के लिए हास्य का इस्तेमाल नहीं करते। वह इसके लिए बहुत गंभीर हैं। बाल ठाकरे अपने भाषण में हास्य के ऐसे तीर मिलाते थे कि मराठी के अलावा कोई भी व्यक्ति हंसता हुआ घर लौट जाता।

राहुल गांधी कभी भी मोदी के विचारों को व्यक्त करने के उच्च मानकों को हासिल नहीं कर सकते, जिस पर खुद स्पीकर ने विश्वास नहीं किया। हर राजनेता की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। उदाहरण के लिए, राहुल मोदी की तुलना में अधिक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जो एक चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। उन्हें मतदाताओं को अपनी योग्यता का एहसास कराने के लिए इस गुण का उपयोग करना चाहिए। विदेशी धरती पर अपने विरोधियों पर हमला करना सही रणनीति नहीं है, भले ही सैम इसकी वकालत करें।

नरेंद्र मोदी और उनके भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह ने हाल ही में कश्मीर घाटी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार, जो 2019 में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल रही है, ने वहां आतंकवाद से निजात पा ली है। फिर भी, हर हफ्ते अखबारों में आतंकवादी हमलों की चर्चा होती है। हम किस पर विश्वास करें? हर हफ्ते मृत नागरिकों और शहीद सैनिकों को दफनाया जाता है या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है! अमित शाह ने घाटी के मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कांग्रेस या नैशनल कांफ्रेंस सत्ता में आती है, तो आतंकवाद अपने सभी घृणित रूपों में इस क्षेत्र में वापस आ जाएगा। दोनों नेता, मोदी और शाह, स्पष्ट रूप से आश्वस्त हैं कि बंदूकें और गोलियां आतंकवाद को खत्म कर देंगी।

यह वह सबक नहीं है जो आयरलैंड या स्पेन और घर के करीब, पंजाब ने अपने स्वयं के मुठभेड़ों से सीखा है। आतंकवाद पर सभी मानक पुस्तकें आपको बताएंगी कि जहां दिमाग से बहकाए गए आतंकवादियों से सख्ती से निपटना होगा, वहीं आतंकवाद को तभी खत्म किया जा सकता है जब वह समुदाय, जिससे आतंकवादी आते हैं, उनके खिलाफ हो जाए। संक्षेप में, आतंकवादियों और आतंकवाद के बीच एक स्पष्ट अंतर है। पहले वाले को खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है, तो युवा भर्ती उनकी जगह ले लेते हैं। आयरलैंड की तरह पंजाब में भी पकड़े गए या मारे गए आतंकवादियों की जगह जल्द ही अन्य युवा भर्ती ने ले ली। जाट सिख किसानों ने सरकार की मदद तभी शुरू की जब उनका जीवन उनके लिए असहनीय हो गया। अकेले बंदूक से कुछ भी हल नहीं हो सकता। लोगों को जीतना होगा। उस परखे हुए समाधान के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

दुर्गापूजा पर आर.जी. कर कांड की छाया

प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा पर आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज कांड की छाया साफ नजर आ रही है। बीते महीने उस सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लंबे अरसे तक जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई थी।इस घटना के विरोध में राज्य की कई दुर्गा पूजा समितियों ने सरकारी अनुदान लेने से इंकार कर दिया है। इधर, राज्य सरकार करीब 43 हजार समितियों को 85-85 हजार रुपए का अनुदान देती है। इसके साथ ही तमाम प्रमुख आयोजन समितियों ने बजट घटा दिए हैं। इसकी वजह यह है कि उनको पिछले साल की तरह प्रायोजक नहीं मिल सके हैं। कोलकाता और उसके आसपास करीब तीन हजार पूजा आयोजित की जाती है। थीम आधारित इस उत्सव में हर साल देश-विदेश की प्रमुख घटनाओं को पंडालों की साज-सज्जा और लाइटिंग के जरिए दर्शाया जाता है। इस साल इस उत्सव पर आर.जी. कर की घटना की छाया नजर आ रही है। कुछ पूजा समितियों ने महिला सुरक्षा को अपनी थीम बनाया है तो एक समिति ने सती दाह को। कोलकाता की नाकतला नबपल्ली दुर्गापूजा समिति न आर.जी. कर की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पूरे पंडाल को ऐसे पोस्टरों और तस्वीरों से सजाने का फैसला किया है। पंडाल की साज-सज्जा में महिला अधिकारों की भी वकालत की जाएगी। कोलकाता के प्रमुख बाजार न्यू मार्केट में एक दुकान समीरन मंडल कहते हैं- इस साल आम लोगों ने आर.जी. कर की घटना को ध्यान में रखते हुए पूजा को उत्सव की तरह नहीं मनाने का फैसला किया है, इसलिए पूजा का आयोजन तो पहले जैसा ही होगा. लेकिन उसमें रंगीनियां नहीं होंगी। पहले जहां दुकानो में रोजाना औसतन 20 से 25 हजार की बिक्री होती थी वह अब घटकर पांच से 10 हजार के बीच यानी आधा या उससे भी कम रह गई है। कपड़ा बिक्रेताओं का दावा है कि इस बार कारोबार पिछले साल के मुकाबले एक-तिहाई है। बंगाल में दुर्गा पूजा का कारोबार 50 हजार करोड़ से ज्यादा है. पूजा के दौरान कॉर्पोरेट घराने 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक खर्च करते हैं. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स पहले ही अनुमान जता चुका है कि 2030 तक दुर्गा पूजा का टर्नओवर मेगा कुंभ मेला के बराबर हो जाएगा जो करीब एक लाख करोड़ रुपए है। कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में हर साल करीब साढ़े चार हजार पूजा आयोजित की जाती है. इनमें करीब दो सौ आयोजन ऐसे हैं, जिनमें हर पूजा में 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है. बाकियों में से हर पूजा में 20 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है. कुल मिलाकर करीब तीन लाख रोजगार पैदा होते हैं. इनमें टैक्सी ड्राइवर और टूर गाइड्स भी शामिल हैं. कोलकाता में एक प्रमुख शापिंग माल के मैनेजर दीप विश्वास के मुताबिक- लोग इस बार उत्सव मनाने के मूड में नहीं हैं। हर साल पूजा के करीब दो महीने पहले से ही प्रमुख बाजारों में भीड़ उमड़ने लगती थी, लेकिन इस साल अपवाद है. इस साल पहले जैसी भीड़ नहीं नजर आ रही है. बिक्री का आंकड़ा भी काफी घट गया है। कोलकाता की एक प्रमुख आयोजन समिति, जिसका बजट करोड़ों में होता है, के संयोजक दीपंकर दास बताते हैं कि इस साल प्रायोजक ही नहीं मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले आधे विज्ञापन भी नहीं मिले हैं. इसकी वजह से बजट में भारी कटौती करनी पड़ी है। आयोजन समितियों के साझा मंच फोरम फार दुर्गोत्सव के अध्यक्ष पार्थ घोष बताते हैं कि पूजा की करीब 50 हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था में 16 सौ करोड़ के खर्च पंडालों और साज-सज्जा पर किया जाता है। इसका 60 फीसदी प्रायोजकों की ओर से मिलता है. लेकिन इस साल कई प्रमुख प्रायोजकों ने या तो अपना हाथ खींच लिया है या फिर बजट में कटौती कर दी है. इससे आयोजन समितियों को भी बजट में कटौती करनी पड़ रही है।

नाश्ते में रवा उपमा खाने से मिलेंगे ये लाभ

नाश्ते में अगर कुछ अच्छा (स्वादिष्ट और हेल्दी) खाने को मिल जाए तो पूरा दिन मूड अच्छा रहता है और आप अपनी प्रॉडक्टिविटी में भी अच्छा परिणाम देखते हैं। बस, जरूर इस बात की है कि हम सभी अपने काम और अपने शरीर की जरूरतों को समझें.लेकिन हममें से ज्यादातर लोग बस यही मात खा जाते हैं। आइए, जानते हैं दिन की बेहतर शुरुआत करने में रवा उपमा किस तरह हमारी सहायता कर सकता है.

रवा खाने के फायदे

- दक्षिणी भारत में सूजी को रवा कहा जाता है। उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्यों में सूजी का हलवा जिस तरह आय दिन घरों में बनता है और सभी बहुत चाव से खाते हैं। ठीक इसी तरह सूजी से तैयार उपमा यानी रवा उपमा दक्षिण भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय भोजन है।
- रवा यानी सूजी गेहूं से तैयार होती है। यह फाइबर से भरपूर होती है इसलिए इसे पचाना हमारे पाचनतंत्र के लिए आसान होता है।
- फाइबर धीमी गति से डायजेस्ट होता है इसलिए यह लंबे समय तक हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है।
- यानी रवा से बना उपमा खाने के बाद जल्दी से भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और आप लंबे समय स्वयं को तक ऊर्जावान महसूस करते हैं।
- रवा उपमा तैयार करते समय इसमें मौसमी सब्जियां मिलाई जाती हैं। यानी इसे खाने से आपको संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। सब्जियों से विटमिन्स और मिनरल्स साथ ही रवा से दिनभर के लिए ऊर्जा।
- रवा उपमा बनाने में मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स का उपयोग किया जाता है। इन्हें खाने से आपको सभी जरूरी अमीनो एसिड्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फॉलिक एसिड और विटमिन्स तथा मिनरल्स की प्राप्ति होती है।
- रवा उपमा फैट यानी वसा और हानिकारक कॉलेस्ट्रोल से पूरी तरह फ्री होता है। इसलिए यह आपके हार्ट की सेहत के लिए भी एक शानदार नाश्ता है। जो हृदय की पंपिंग को सही बनाए रखने और अपने पौषक तत्वों से रक्त का प्रवाह बनाए रखने का काम करता है।
- रवा उपमा खाने में बहुत अधिक स्वादिष्ट और साथ ही सेहत के गुणों से भरपूर होता है। इसलिए साउथ इंडिया से निकलकर इस फूड ने देश के हर हिस्से और घर में अपनी जगह बना ली है।
- आज के समय में पोहा (मुख्य रूप से मध्य भारतीय आहार) दही चूड़ा (मुख्य रूप से बिहार का भोजन) और रवा उपमा तथा इडली (दक्षिण भारतीय भोजन) अपने-अपने राज्यों की सीमाए पार कर नैशनल फूड बन चुके हैं।
- इसकी खास वजह है कि इन फूड्स को तैयार करने में कम समय लगता है। ये पौषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कम ऑइली होने के कारण फिटनेस को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके साथ ही पाचन के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं तो इन्हें खाने के बाद आलस भी नहीं आता है।

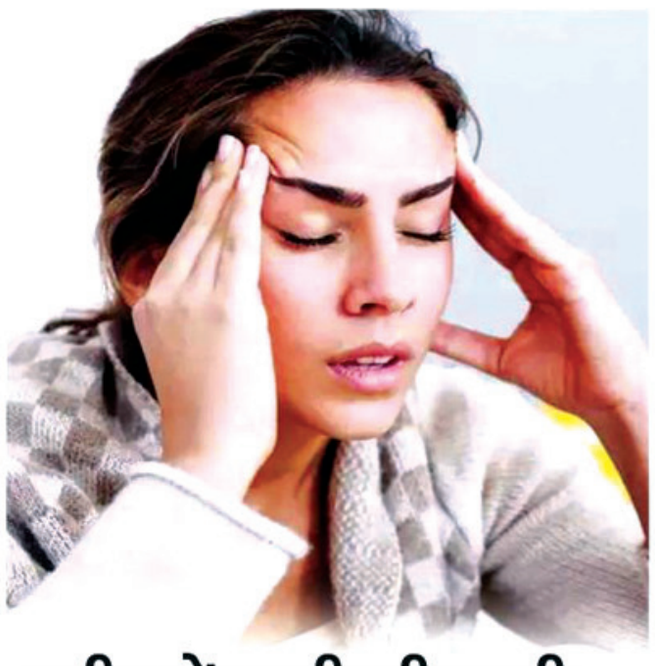

शरीर में पानी की कमी को हल्के में ना लें

शरीर में पानी की कमी को हल्के में ना लें। ये आपको कई गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल सकती है. चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, हमारे शरीर का 30 प्रतिशत हिस्सा तरल है और बाकी 70 प्रतिशत में अस्थि और मज्जा शामिल है। यही वजह है कि जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। क्योंकि मनुष्य बिना भोजन के कुछ समय रह सकता है लेकिन बिना पानी के रहना असंभव होता है। यानी जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पानी तो हम सभी लोग पीते हैं लेकिन ज्यादातर लोग शरीर की जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। यही कारण है कि हमारे समाज में बड़े स्तर पर सूखे की बीमारी से पीड़ित पेशंट देखे जा सकते हैं। खासतौर पर गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन के मरीजों की मानो बाढ़ आ जाती है।

हल्के में ना लें यह समस्या

- आमतौर पर शरीर में पानी की कमी होने को हम सभी बहुत हल्के में लेते हैं। यह एक बड़ी वजह है कि डिहाइड्रेशन के कारण बड़ी संख्या में रोगियों की मृत्यु हो जाती है। आइए, यहां जानते हैं शरीर के उन सामान्य लक्षणों के बारे में जो आपके शरीर में पानी की कमी को दर्शाते हैं। ताकि इन लक्षणों के आधार पर आप तुरंत इस समस्या से निजात पा सकें.

पानी की कमी के सामान्य लक्षण

- जब शरीर में पानी की कमी होती है तो आपके होंठ बहुत सूखे-सूखे हो जाते हैं और उनकी बाहरी त्वचा फटने लगती है। कई बार होठों से खून भी आने लगता है।
- पानी की कमी के कारण गला लगातार सूखा बना रहता है और बार-बार प्यास लगने पर पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं मिटती है।
- शरीर में पानी की कमी के कारण सीने पर हल्की जलन, पेट में एसिडिटी या असहजता हो सकती है। साथ ही मुंह से सांसों के साथ लगातार दुर्गंध आती है। ब्रश करने के बाद भी आप सांसों की दुर्गंध फील कर पाते हैं।

यूरिन, स्किन और मसल्स पर असर

- जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब गाढ़े पीले रंग का आता है। इसके साथ मात्रा में सामान्य से कम होता है और पेशाब के बाद प्राइवेट पार्ट में जलन या खुजली की समस्या हो सकती है।
- डिहाइड्रेशन से जूझ रहे लोगों के शरीर की त्वचा भी बहुत रूखी और बेजान नजर आती है। जो लोग लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं, उनकी त्वचा पर कम उम्र में ही झुर्रियां नजर आने लगती हैं।
- पानी की कमी से मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और जकड़न की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही सिर में लगातार दर्द बना रहता है। इस कारण रोगी का चेहरा मुर्झाया हुआ और तेजहीन लगता है।
- जो लोग शरीर की जरूरत के अनुसार पानी नहीं पीते हैं, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ देखे जा सकते हैं। इन लोगों की आंखें अंदर धसने लगती हैं और इन्हें हर समय कमजोरी का अहसास बना रह सकता है।

सेहत समस्याओं से निजात पाने के लिए पुदीने के घरेलू नुस्खे

गर्मियों का मौसम आते ही भूख कम लगने लगती है, पेट व त्वचा की गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में ऐसी चीजें खाने की जरूरत होती है जो आपको ठंडक दे और पुदीना इस मौसम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। गर्मियों में पुदीना या मिंट के अलग-अलग इस्तेमाल से कई सेहत लाभ पाए जा सकते हैं। आइए, जानते हैं पुदीना के ये 8 बेहतरीन घरेलू नुस्खे

- पेट की गर्मी को कम करने के लिए पुदीने का प्रयोग बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा यह पेट से संबंधित अन्य समस्याओं से भी जल्द निजात दिलाने में लाभकारी है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
- दिनभर बाहर रहने वाले लोगों को पैर के तलवों में जलन की शिकायत रहती है, ऐसे में उन्हें फ्रिज में रखे हुए पुदीने को पीसकर तलवों पर लगाना चाहिए ताकि तुरंत राहत मिल सके। इससे पैरों की गर्मी भी कम होगी।
- सूखा या गीला पुदीना छाछ, दही, कच्चे आम के पने के साथ मिलाकर पीने पर पेट में होने वाली जलन दूर होगी और ठंडक मिलेगी। गर्मी हवाओं और लू से भी बचाव होगा।
- अगर आपको अक्सर टॉन्सिल्स की शिकायत रहती है और इसमें होने वाली सूजन से भी आप परेशान हैं तो पुदीने के रस में सादा पानी मिलाकर इस पानी से गरारे करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
- गर्मी में पुदीने की चटनी का रोजाना सेवन सेहत से जुड़े कई फायदे देता है। पुदीना, काली मिर्च, हींग, सेंधा नमक, मुनक्का, जीरा, छुहारा सबको मिलाकर चटनी पीस लें। यह चटनी पेट के कई रोगों से बचाव करती है व खाने में भी स्वादिष्ट होती है। भूख न लगने या खाने से अरुचि होने पर भी यह चटनी भूख को खोलती है।
- पुदीने व अदरक का रस थोड़े से शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। वहीं अगर आप लगातार हिचकी आने से परेशान हैं तो पुदीने में चीनी मिलाकर धीरे-धीरे चबाएं। कुछ ही देर में आप हिचकी से निजात पा लेंगे।
- पुदीने की पत्तियों का लेप करने से कई प्रकार के चर्म रोगों को खत्म किया जा सकता है। घाव भरने के लिए भी यह उत्तम है। इसके अलावा गर्मी में इसका लेप चेहरे पर लगाने से त्वचा की गर्मी समाप्त होगी और आप ताजगी का अनुभव करेंगे।
- पुदीने का नियमित रूप से सेवन आपको पीलिया जैसे रोगों से बचाने में सक्षम है। वहीं मूत्र संबंधी रोगों के लिए भी पुदीने का प्रयोग बेहद लाभदायक है। पुदीने के पत्तियों को पीसकर पानी और नींबू के रस के साथ पीने से शरीर की आंतरिक सफाई होगी।

हल्की-हल्की भूख में लें इन तीन सूप का मजा

नाश्ते के बाद और लंच से पहले वाली भूख को हैंडल करने के लिए ज्यादातर लोग चाय, कॉफी या फास्ट फूड और डिब्बाबंद फूड्स का सेवन करते हैं। लेकिन हम यहां आपको चंद मिनट में तैयार होनेवाले उन 3 खास सूप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको 'अपनी तो लाइफ सेट है!' जैसा फील देंगे.

वेजिटेबल सूप

- मौसमी सब्जियों के साथ आप मिक्स वेज सूप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी एक सब्जी को उबालकर उसका सूप बनाएं और शिमला मिर्च, बीन्स, मशरूम, हरी प्याज और आलू को महीन टुकड़ों में काटकर इन्हें अलग उबाल लें।
- पहले से तैयार सूप में इन सब्जियों को मिलाएं और अपने स्वाद के हिसाब से काला नमक, जीरा पाउडर आदि मिलाएं। ध्यान रखें सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर मिलाया जाता है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन अधिक मात्रा में इसे मिलाने से बचें। नहीं तो यह आपके वजन को बढ़ाने की वजह बन सकता है।

चुकंदर का सूप

- चुकंदर का सूप बनाने के लिए आप टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, काली मिर्च का पाउडर और नींबू का रस जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। ये सभी बहुत पौष्टिक और सेहत को फिट रखनेवाली चीजें हैं।
- चुकंदर का सूप तैयार करने के लिए एक कुकर में बारीक कटे प्याज और लहसुन भून लें। इसके बाद कटे हुए चुकंदर, आलू और टमाटर डालकर भूनें। इन्हें दो मिनट पकाने के बाद कुकर को बंद कर दें और इसमें धीमी आंच पर 4 सीटी आने दें।
- तैयार मिश्रण को मिक्सी में डालकर पीसें और गाढ़ा लिक्विड तैयार करें। इसे छान लें और काली मिर्च पाउडर तथा नींबू का रस मिलाकर सूप तैयार करें और इसे हरी धनिया पत्तियों के साथ गार्निश करके सूप का लुत्फ उठाएं।

मूंग दाल का शोरबा

- मूंग दाल का शोरबा मात्र 10 मिनट में तैयार हो जाता है। इसके लिए आप बिना छिलके की मूंग दाल को धुलकर कुकर में 3 से 4 सीटी लगा लें। इसे तैयार करते समय आपको पानी की मात्रा सामान्य दाल बनाने से दोगुना रखें और गैस की धीमी आंच पर रखकर ही पकाएं।
- अब इसमें हरी धनिया पत्ती, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा कच्चा प्याज मिलाकर तड़का लगा दें। मसलों के नाम पर इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर का उपयोग करें, हल्का काला नमक मिलाएं और काली मिर्च पाउडर मिक्स करके गर्मागर्म शोरबा का लुत्फ उठाएं।

वजन घटाने के लिए लोग न जानें कितनी प्रकार की डायट फॉलो करते हैं। लेकिन अपने आपको भूखा रखकर लंबे समय तक बिना सोचे-समझे किसी भी प्रकार की डायट का पालन करना मुश्किल हो जाता है। वजन घटाना कोई आसान काम नहीं है। शरीर की एक्सट्रा चर्बी को निकालने के लिए नियमित व्यायाम के साथ कैलोरीज भी बर्न करनी पड़ती हैं। इसके लिए आयुर्वेद के पास ऐसे कई तरीके हैं, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी और आपको वजन कम करने में आसानी होगी। ये तरीके बेहद आसान हैं, लेकिन आपको इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। आइए जानते हैं क्या हैं वो तरीके जिसे मोटापा घटाने के लिए आयुर्वेद में अहम माना गया है.

खाली पेट इन चीजों का सेवन करने से घटता है मोटापा

गर्म पानी के साथ घी और नींबू

200 मिलीलीटर पानी के साथ थोड़ा सा नींबू या घी का सेवन करने से पेरिस्टलसिस में सुधार होता है, जो कि वेस्ट और खाने की गति को नीचे की ओर ढकेलता है। यदि आपका शरीर वात या पित्त प्रकार का है, तो आप इससे आपका पाचन तंत्र चिकना होगा जिससे कब्ज की समस्या दूर होगी।

डायजेस्टिव चाय

आजकल, बाजार में आयुर्वेदिक चाय की ढेर सारी वैराइटीज उपलब्ध हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप घर पर अपनी चाय खुद ही बना लें। इसके लिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया के बीज, 1 इलायची और थोड़ी सी अजवाइन को लेकर 500 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें, जब तक पानी की मात्रा आधी न हो जाए।

मेटाबोलिज्म बढ़ाने के लिए चाय आजमाएं

अपने मेटाबोलिज्म को तेज बनाने के लिए आप दालचीनी, इलायची, लौंग, कद्दूकस की हुई अदरक, काली मिर्च, हल्दी और स्टार ऐनीज को 500 मिली पानी में उबालें। यह पानी आधा हो जाए तब इसमें आधा नींबू और कोकोनट शुगर मिलाएं। चाय शरीर की गर्मी बढ़ाकर चयापचय में सुधार करके वजन कम करने में मदद करेगी।

कच्चे फल

सुबह खाली पेट हर्बल चाय पीने के बाद, कच्चे फलों का सेवन करें जो प्रकृति में थोड़े से कसैले हो सकते हैं। ग्रीन और रेड एपल, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, अनानास, आंवला और अनार जैसे फलों को ही चुनें। यह फल शरीर में वॉटर रिटेंशन को कम करते हैं और आपकी त्वचा में कोलेजन को बढ़ाते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है।

सिलेरी जूस (अजमोद का रस)

तनाव से बचने के लिए आयुर्वेद कच्चे फल और पकी या उबली हुई सब्जियां खाने की सलाह देता है। ऐसी स्मूदी लेने से बचें जिसमें फल, सब्जियां, दूध और दही का मिश्रण शामिल हो। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों के संचय का कारण बन सकता है। बल्कि पेट की ब्लोटिंग और अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए एक चुटकी सेंधा नमक और नारियल तेल के साथ सिलेरी का जूस लें।

वजन घटाने के पांच बुनियादी नियम भी जानें

- जब आपको भूख लगे तब ही खाएं।
- सूर्यास्त के बाद न खाएं।
- इंटरमिटेंट फास्टिंग करें जिसमें 16 घंटे के तक कुछ भी न खाएं। इससे आपकी ऊर्जा तो बढ़ती है साथ में दिमाग पर कंट्रोल रहता है।
- कच्चे फल खाने के बाद पका हुआ भोजन करें।
- आपका पेट केवल आपकी मुट्ठी के आकार का है। अपनी भूख से 80 प्रतिशत भोजन कम खाएं, ताकि खाना पचाने वाले रस अपना काम आसानी से कर सकें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

हजारीबाग में होगा भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का समापन

नईदिल्ली। झारखंड चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का समापन हजारीबाग में होगा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को एक रैली को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि जेएसएस ने चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की नकल की है। हेमंत सोरेन को हिसाब देना चाहिए... मध्य प्रदेश में इतने दिनों से लाडली बहना योजना चल रही है, महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना चल रही है, छत्तीसगढ़, ओडिशा में जब से हमारी सरकार बनी है तब से बहनों के खातों में हम पैसे डाल रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि रोजगार बड़ा सवाल है, उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन क्या उन्होंने एक नौकरी के लिए एक पैसा भी दिया? पहले उन्होंने नौकरी नहीं दी और अब वे बच्चों को दौड़ा रहे हैं।

सरकार घबराई हुई है प्रधानमंत्री परेशान हैं: जयराम

नईदिल्ली। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश लगातार मोदी पर हमलावर रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर से जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान के बहाने रमेश ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान 400 पार और संविधान बदलने की बात की। हमारे गैर-जैविक पीएम चुप रहते हैं और दूसरों से बयान दिलवाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीन काले कानूनों को वापस लाने की मांग बीजेपी की ओर से हर दिन आती है। अपना हमला जारी रखते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम और स्वघोषित चाणक्य ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वे आरक्षण पर 50% की सीमा हटाएंगे या नहीं इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्य चुनावों में ये बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं।

दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन

नईदिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी दौरान एमके स्टालिन ने राज्य में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए शीघ्र धन जारी करने पर मांग की। डीएमके सूत्रों ने खुलासा किया कि स्टालिन का लक्ष्य चेन्नई मेट्रो और सार्वभौमिक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी पहल के लिए वित्तीय सहायता सुरक्षित करना था। स्टालिन की यात्रा इन फंडों के आवंटन में देरी पर चिंताओं के बीच हो रही है, तमिलनाडु सरकार कथित तौर पर पीएम-एसएचआरआई स्कूलों की योजना को एसएसए फंड जारी करने से जोड़ने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव से नाखुश है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के अलावा, स्टालिन के कांग्रेस के नेताओं और इंडिया ब्लॉक के अन्य सदस्यों के साथ भी चर्चा करने की उम्मीद है। यह यात्रा 28 सितंबर को कांचीपुरम में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक रैली से पहले हो रही है, जहां विपक्षी गठबंधन के नेता इकट्ठा होंगे।

कांग्रेस लोगों की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है

नईदिल्ली। कर्नाटक में मुडा विवाद के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में आती है, वहां गरीब, दलित, एससी-एसटी-ओबीसी समाज के लोगों की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड, हरियाणा में दामाद और कर्नाटक में बीवी इन सभी को लाभार्थी बनाती है, इसलिए ये जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहलाती है। भाजपा नेता ने कहा कि सत्ता में आकर लूटना कांग्रेस का काम है। कर्नाटक में करोड़ों रुपये के मुडा घोटाले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने वही किया जो कोई सर्टिफाइड लुटेरा करेगा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर मुदा घोटाले में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की अनुमति क्यों नहीं देते?

दिल्लीवालों को केजरीवाल ने दिलाया भरोसा

नईदिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर की सभी सड़कों का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से तत्काल मूल्यांकन कराने को कहा है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सीएम आतिशी को अगले तीन-चार दिनों के भीतर मूल्यांकन पूरा करने के लिए कहा है। हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल ने बताया कि उनके कारावास के दौरान कई परियोजनाओं में देरी हुई। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि रुकी हुई परियोजनाएं अब फिर से शुरू होंगी और दिल्ली के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने का वादा किया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैंने कल भी आतिशी के साथ डीयू का दौरा किया था। सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी। आज हम यहां आये हैं। इसलिए, मैं आतिशी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगले 3-4 दिनों में दिल्ली की सभी पीडब्ल्यूडी सड़कों का आकलन करें।

एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना करें कांग्रेस : अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री का राहुल से सवाल, खरीफ और रबी की फसल कौन सी है?

चंडीगढ़। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने दावा किया कि जनसभा में जनता का उत्साह बता रहा है कि इस बार भाजपा की जीत की हैट्रिक लगना तय है। शाह ने संबोधन के शुरूआत में कहा कि ये हरियाणा की भूमि बलिदान व वीरता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि शक्ति और समृद्धि की भूमि है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जम्मू-कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार की शुरुआत हरियाणा से की थी और उन्होंने वादा किया था कि 40 वर्षों से हमारे सेना के जवानों द्वारा की जा रही वन रैंक-वन पेंशन की मांग को पूरा करेंगे। 40 वर्षों तक कांग्रेस वन रैंक-वन पेंशन लागू नहीं कर पाई, आपने मोदी जी को सेवा का मौका दिया और मोदी जी ने वन रैंक-

वन पेंशन को लागू किया। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले वन रैंक-वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू कर दिया गया है।

कांग्रेस पर वार करते हुए शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में न डीलर बचे न ही दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुलफॉर्म मालूम है आपको? खरीफ और रबी की फसल कौन सी है, क्या आपको मालूम है। पूरे देशभर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद कीजिए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दें कि देश में आपकी कौन सी सरकार एमएसपी पर 24 फसल खरीदती है? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदते है, बताइए जरा... अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे क्योंकि आपके समय में बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे।

विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जाकर ये कहते हैं कि हम सभी आतंकियों और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। 40 हजार लोग जम्मू-कश्मीर में मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हो गए और आप कहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दोगे। अरे राहुल बाबा, हिम्मत है तो हरियाणा में आकर वही भाषण दीजिए। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, विदेश जाकर कहते हैं कि हम एसटी-एससी-ओबीसी समुदाय का आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और ?अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, कैसे समाप्त कर दोगे, सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं कि जब तक संसद में भाजपा का एक भी सांसद है, तब तक आप आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकारा : नड्डा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर चुनाव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बूथ-कैप्चरिंग, गोलीबारी या आतंकवादी हमलों का कोई निशान नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव देखने के लिए दुनिया भर के 16 देशों के राजदूत यहां आए थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब जम्मू-कश्मीर के लोग बुलेट के बजाय बैलेट की शक्ति को चुन रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं, जो इस बात का प्रतिबिंब हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस चुनाव में पिछले चुनाव की भांति कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई और कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि 16 देशों के एंबेसडर यहां का चुनाव देखने आए थे और उन्होंने देखा कि कैसे यहां की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण और प्रजातंत्र में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया।

इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ऐतिहासिक इवेंट है, जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को नकार कर बैलेट का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि जम्मू औसतन साल में 100 दिन बंद रहता था, पिछले पांच साल में जम्मू न बंद हुआ और न ही कोई हड़ताल हुई। जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकार दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अनुच्छेद-370 के समाप्त होने से पहले यहां लगभग 300-400 आतंकवादी पैदा होते थे और उन्हें आतंकी घोषित किया जाता था और आज ये संख्या सिर्फ 4 है।

विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि चिंता की बात ये है कि जब युवाओं ने आतंक को नकार दिया, जब यहां के युवा शांति, स्थिरता और विकास की ओर चल पड़ा है, तो पीडीपी, एनसी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां आज उन लोगों का साथ दे रही हैं, जो देश के विरोध में काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एनसी का घोषणा पत्र कहता है कि हम आतंकवादियों को जेल से रिहा करेंगे। हम एलओसी से ट्रेड शुरू करेंगे। इसके अलावा वे पाकिस्तान से वार्ता करने को भी बढ़ावा देता है। इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर दे रहा है। जो कह रहा है कि भारत में एनसी और कांग्रेस हमारा एजेंडा चला रहे हैं।

कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया आतंकवाद पनपाने का पाप : आदित्यनाथ

श्रीनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जम्मू के रामनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की ताकत देखनी है तो उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देखिए। 500 साल बाद अयोध्या धाम में भव्य मंदिर बना है और उसमें रामलला विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि बाधा डालने वाले लोगों का कहना था कि राम मंदिर बना तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन यह नया भारत है और यह अपनी रक्षा करना जानता है।

योगी ने कहा कि पिछले साढ़े

सात साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं। और डबल इंजन सरकार के विकास को देखिए, उस विकास का अधिकार जम्मू-कश्मीर का भी है। भाजपा नेता ने कहा कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने धरती के स्वर्ग को सांप्रदायिक उग्रवाद का गोदाम बना दिया और लोगों का शोषण किया, परिवारवाद और भ्रष्टाचार विकसित किया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया? कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वे पापी हैं।

यूपी सीएम ने कहा कि धारा 370 हटाने पर भी उन्होंने वही कहा जो उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35ए हटने से जम्मू-कश्मीर को विकास मिला। यह आतंकवादी राज्य से पर्यटन राज्य बन गया। यहां हाईवे और आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना की जा रही है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा पुल बन रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने युवाओं के हाथ में टैबलेट नहीं बल्कि तमंचा दिया। लेकिन मोदी सरकार उन्हें रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाना आतंकवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक उग्रवाद को वापस लाने का एक कुत्सित प्रयास है।

पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री : उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बीच वार-पलटवार का दौर भी जारी है। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष और गांदरबल और बडगाम से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जम्मू में जो हालात हैं, आज जम्मू में जो आतंकवाद है, आज हमारे वीर जवानों को निशाना बनाया जा रहा है- बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि 2014 के बाद जम्मू में आतंकवाद क्यों फैला और पिछले 3 सालों में आतंकवाद का ग्राफ अचानक क्यों बढ़ गया। यह उनकी विफलता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब आप जम्मू-कश्मीर आते हैं तो आप (भाजपा) उन्हें (पाकिस्तान को) नहीं पकड़ते। जब आप जम्मू-कश्मीर आते हैं तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहां आते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारी बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्द समाप्त

कानपुर। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। कानपुर में भारी बारिश की वजह से अंपायर ने पहले दिन के खेल को जल्द समाप्त करने की घोषणा की है। देर रात भारी बारिश की वजह से आज खेल की शुरुआत भी एक घंटे की देरी से हुई थी। टॉस नौ बजे की जगह सुबह 10 बजे हुआ था। वहीं, मैच शुरू सुबह साढ़े नौ बजे की जगह सुबह साढ़े 10 बजे हुआ था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं था, जबकि बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने दो बदलाव किए थे। नाहिद राणा और तस्कीन अहमद यह मैच नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह खालिह अहमद और तैजुल इस्लाम को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया।

बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। फिलहाल मोमिनुल हक 40 रन और मुशफिकुर रहीम छह रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच अब तक चौथे विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी हो चुकी है। मोमिनुल टेस्ट में अपने 20वें अर्धशतक के करीब हैं। हालांकि, खराब रोशनी की वजह से खेल को रोक दिया गया। अंपायर ने सभी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाने कहा। इसके बाद मैदान को कवर्स से ढक दिया गया है।

जाकिर हसन और शदमान इस्लाम ने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि, ज्यादा डॉट बॉल खेल लेने की वजह से जाकिर पर दबाव आया और वह इस दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे। जाकिर को आकाश दीप ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। वह 24 गेंद में बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे। इसके बाद आकाश दीप ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शदमान इस्लाम को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह 36 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने चार चौके लगाए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 264 अंक टूटा निफ्टी 26,178 पर बंद

नईदिल्ली। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में मुनाफावसूली के कारण भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को फिसलकर रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 264.27 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट लेकर 85,571.85 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 142.13 अंक या 0.16 प्रतिशत चढ़कर 85,978.25 के नए रिकॉर्ड इंट्रा-डे उच्च स्तर पर पहुंचा था। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 37.10 अंकों या 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,178.95 पर बंद हुआ, जबकि दिन के दौरान यह 61.3 अंक या 0.23 प्रतिशत बढ़कर 26,277.35 के सर्वकालिक इंट्रा-डे उच्च स्तर पर पहुंचा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। सन फार्मा, रिलायंस, टाइटन, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे।

सरकार विशेष स्टील के लिए पीएलआई योजना करेगी शुरू

नईदिल्ली। इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि सरकार विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के एक और दौर पर काम कर रही है, क्योंकि इसके पहले दौर की प्रतिक्रिया उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के इस्पात शिखर सम्मेलन 2024 में यह बात कही। पौंड्रिक ने कहा कि विशेष इस्पात अब भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां और अधिक काम करने की जरूरत है। सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाई, लेकिन इसका उठाव उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने कहा, '' इसलिए हम पीएलआई का एक और दौर ला रहे हैं ताकि हमें विशेष इस्पात कारोबार में अधिक रुचि मिल सके।''

भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.5-7% की दर से बढ़ेगी

नईदिल्ली। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर आधार पर 6.5 से सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए यह वृद्धि दर सराहनीय है। बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जबकि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कीमतों पर (नॉमिनल) वृद्धि दर 11 प्रतिशत होगी। नागेश्वरन ने कहा, '' भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में स्थिर आधार पर 6.5 से सात प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में यह बेहद अच्छी उपलब्धि है।''

स्पाइसजेट ने बकाया जीएसटी चुकाया

नईदिल्ली। कर्ज में डूबी विमान कंपनी स्पाइसजेट ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपना माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का पूरा बकाया चुका दिया है। स्पाइसजेट पर 145 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी बकाया था। उसने पिछले सप्ताह पात्र संस्थागत नियोजन के जरिये 3,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि उसने पूरे बकाया जीएसटी का भुगतान कर दिया है। स्पाइजेट के 3,000 करोड़ रुपये जुटाने से संबंधित प्रारंभिक नियोजन दस्तावेज के अनुसार, एयरलाइन पर 15 सितंबर तक 145.1 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया था। विमान कंपनी 3,000 करोड़ रुपये की नई पूंजी प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों के जुलाई और अगस्त के बकाया वेतन के साथ-साथ जून के लंबित वेतन का भी भुगतान कर दिया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत

सतीश सिंह

डॉ. राममनोहर लोहिया को समाजवादी सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। उनके अनुसार, समाजवाद ही वह सिद्धांत है, जिस पर चलकर वंचित तबके को भी विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। समाजवाद की परिभाषा के अनुसार, यह एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें उत्पादन के साधनों और संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और सरकार द्वारा यह नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसका मूल सार यह है कि उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व समाज में समानता लाने में अहम भूमिका निभाता है।

इसी वजह से दुनिया के अनेक देशों में इसे विकास का सबसे बेहतर सिद्धांत माना जाता है। वैसे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात यहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकारी और निजी, दोनों हाथों में है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूंजीवाद और समाजवादी सिद्धांतों का मिश्रण है। समाजवादी सिद्धांत के अनुरूप डॉ. लोहिया समावेशी विकास के समर्थक थे। वह देश के विकास में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते थे। यह तभी मुमकिन था, जब देश के सभी लोग आत्मनिर्भर हों, यानी कोई रोजगार करें या स्वरोजगार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के भी वे पैरोकार थे अर्थात सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र हों, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में कुछ निश्चित जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें, क्योंकि तभी हमारा समाज और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के तौर-तरीकों के बारे में महात्मा गांधी और डॉ. लोहिया की विचारधारा में समानता थी।

डॉ. लोहिया के अनुसार, देश की ग्रामीण आबादी को सबल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है। डॉ. लोहिया का मानना था कि देश में पूंजी और तकनीकी कौशल की कमी है। इसलिए यूरोप या रूस की विकासात्मक रणनीति को अपनाकर भारत में विकास की गति को तेज नहीं किया जा सकता है। वे चाहते थे कि देश में गांधी जी के कुटीर उद्योग और नेहरू के भारी उद्योग के नजरिये के बीच का रास्ता अपनाया जाए, ताकि देश में समावेशी विकास को बल मिल सके।

उनके अनुसार, कृषि और औद्योगिक विकास की गति में समानता हो, ताकि किसानों व ग्रामीणों को भी विकास की राह पर आगे लेकर बढ़ा जा सके। डॉ. लोहिया चाहते थे कि रेल, इस्पात आदि भारी उद्योग केंद्र सरकार की देखरेख में चलें, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन जिलों, तहसील और गांवों पर छोड़ दिया जाए। वह युवाओं और महिलाओं को विशेष तरजीह देते थे। उनका मानना था कि युवा देश के कर्णधार हैं, क्योंकि वे एक लंबे समय तक देश के विकास में सहभागी बने रहते हैं। इसलिए उन्हें कौशलयुक्त बनाने की जरूरत है, ताकि वे बेरोजगार नहीं रहें और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सतत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। डॉ. लोहिया लिंग के आधार पर भेदभाव करने के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का स्थान देकर लैंगिक भेदभाव की समस्या को जड़ से खात्मा किया जा सकता है। वह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहते थे।

डॉ. लोहिया जानते थे कि भारत जैसे बड़े देश में वंचित तबकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, देश में अकाल पड़ने पर भोजन की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के डाल्टनगंज में चल रहे 'घेरा डालो' आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया था। वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्षधर थे, लेकिन किसी भी मामले में एकतरफा कारोबार के हिमायती नहीं थे, यानी आयात और निर्यात बराबर होना चाहिए।

क्रमशः ...

नितिन ने ली सदस्यता अभियान को लेकर बैठक, हर जिले का टारगेट 20 प्रतिशत बढ़ाया, बड़े शहरों को विशेष टारगेट

हम 60 लाख सदस्यता का लक्ष्य अर्जित करेंगे -नवीन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ भाजपा को सदस्यता का लक्ष्य 10 लाख बढ़ाकर 60 लाख सदस्यता का लक्ष्य दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को सदस्यता प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्षों और जिला सदस्यता प्रभारियों की बैठक ली। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, भूपेंद्र सवन्नी, निरंजन सिन्हा, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, भारत लाल वर्मा, रामजी भारती, जगदीश (रामू) रोहरा, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, सह प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, बस्तर संभाग प्रभारी रजनीश सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, राजीव अग्रवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय, जिला अध्यक्ष रायपुर शहर जयंती पटेल, भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में जिला सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक सदस्य पूरी सक्रियता के साथ सदस्यता अभियान में लगा हुआ है। सभी चीजों का आँकलन करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए सदस्यता का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे अब 10 लाख बढ़ाकर 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही श्री नवीन ने हर जिले का लक्ष्य 20 प्रतिशत बढ़ाया है। भाजपा के सदस्यता अभियान में दिख रही एकजुटता के दृष्टिगत श्री नड्डा ने यह लक्ष्य दिया है। श्री नवीन ने कहा लक्ष्य के आधार पर हमने आँकलन कर प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्षों के साथ बैठकर सदस्यता अभियान में 10 लाख अतिरिक्त सदस्य बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की है और 60 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को हम लोग हासिल करेंगे, इसके लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है। श्री नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य के विकास में मात्र 8 महीने में ही उन सारे वादों को भी पूरा किया है जो वादे पूर्व की कांग्रेस सरकार 5 वर्षों में पूरा नहीं कर पाई। भाजपा की सरकार ने 8 महीने में ही मोदी की गारंटी के तहत के गए अधिकांश वादे भी पूरे किए हैं। जनता हमारे साथ है और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस अभियान में दिख रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा में कांग्रेस की शुक्रवार से शुरू हुई न्याय पदयात्रा पर तीखा कटाक्ष करते हुए कांग्रेस शासनकाल के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार गिनाए और कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के साथ जितना अन्याय किया है, उनको उन अन्याय का हिसाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता से इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अजा वर्ग के युवा अभ्यर्थियों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा था! छत्तीसगढ़ वह दिन भी भूला नहीं है कि किस प्रकार पीएससी के घोटाले में पूरी सरकार इन्वॉल्व थी! प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास को केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था, इसलिए गरीबों का आवास छीनने का गुनाह किसने किया! वहीं कांग्रेस की सरकार ने घोटालों का सिलसिला चलाया! किस प्रकार शराब घोटाले में सरकार पूरी तरह से संलिप्त नजर आई। भगवान के नाम पर महादेव सट्टा एप बनाकर किस प्रकार से कांग्रेस की पिछली सरकार के मुखिया और उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के नेता खुद उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन का बाजार बनाया हुआ था। श्री नवीन ने कहा कि इन सब गलत कृत्यों के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो अन्याय किया है, उसके लिए कांग्रेस नेताओं को पछतावा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए।

युवा मतदाताओं को साधने युवाओं में लोकप्रिय जयदीप गुप्ता बालोद जिला के सदस्यता अभियान प्रभारी नियुक्त

बालोद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा प्रधानमंत्री को प्रथम सदस्य बनाया गया। सदस्यता अभियान के माध्यम से देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा , पर्व मनाकर अपना विस्तार कर रही है. भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी के निर्देशन पर एवं व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री लाफ़चंद बाफना जी के अनुसंसा पर दुर्ग संभाग के प्रभारी कांतिलाल बोथरा जी व सह प्रभारी प्रमोद जैन जी ने भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के लिए व्यापारी प्रकोष्ठ की तरफ से बालोद जिले लिए जयदीप गुप्ता को प्रभारी बनाया है वही सह प्रभारी के रूप में रमेश जैन को नियुक्त किया गया है । जयदीप गुप्ता ने पूरे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुवे कहा कि भाजपा पूरे 6 सालो में इस सदस्यता अभियान को एक महापर्व के रूप मनाती है ऐसे में आज मुझे बालोद जिले का प्रभारी बनाया है ऐसे बालोद जिले में हम सभी व्यापारी प्रकोष्ठ के लोग मिल कर शत प्रतिशत सदस्य बनाएंगे साथ ही इस महापर्व में नये लोगो को भी बड़ी सख्या में सदस्य बनाने का सकल्प दिलाएंगे। जयदीप गुप्ता पहले से ही दल्ली राजहरा मंडल में वार्ड वार्ड व आस पास के गांव में सदस्यता अभियान चला रहे है।

दशकों से सम्हाल रखा है युवाओं को जोड़ने का बीड़ा– जयदीप गुप्ता बालोद जिले के सक्रिय नेता है जमीनी रूप से कार्य करने वालो में से एक नेता है , जिन्होंने जनभागीदारी अध्यक्ष का दायित्व निभाते हुए उस वक़्त से ही युवाओं की फौज तैयार करने वाले जयदीप गुप्ता ने लाफ़चंद बाफना, कांतिलाल बोथरा, पवन साहू, प्रमोद जैन, राकेश यादव, चेमन देशमुख व गोविंद वाधवानी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि मुझे जो जिमेदारी दी गयी है मैं जिमेदारी से कार्य करूंगा ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ने की कोसिस करूंगा। दल्लीराजहरा नगर में हर्ष का माहौल बना हुवा है सुरेश जायसवाल, स्वाधीन जैन, विशाल मोटवानी, मनोज दुबे, महेन्द्र सिंग, आशीष लालवानी , हितेश कुमार, योगेन्द्र सिन्हा, आलोक जैन, रुचिन जैन, विकाष ओतवानी, प्रकाश साहू, साहिल स्वर्णकार, पुनीत पटेल, अर्जुन यादव, जीतू ठाकुर, अभिजीत श्रीवास्तव, वैभव तिवारी, मुकेश खस , बिट्टू कनोजिया, देव पिपरे, राहुल सिंग ने बधाई दी है ।

बहुचर्चित शराब घोटाला: नकली होलोग्राम प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने 2500 पन्नों का कोर्ट में पेश किया चालान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी प्रकरण मामले में आरोपियों के खिलाफ आज कोर्ट में चालान पेश हुआ है. राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले में नकली होलोग्राम का बड़ा जखीरा ईओडब्ल्यू ने बरामद किया था. नकली होलोग्राम की कड़ी छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और उत्तरप्रदेश तक जुड़ रही थी. इसके बाद ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की थी. नकली होलोग्राम प्रकरण पर ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार आरोपी अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुलारी और दिलीप पांडे के खिलाफ चालान पेश किया है. गौरतलब है सूबे के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जांच कर मुख्य सरगना अनवर ढेबर की धनेली स्थित मैदान से बड़ी मात्रा में नकली अधजले होलोग्राम का जखीरा बरामद किया था. साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों पर सिंडिकेट बनाकर अवैध रूप से शराब बेचकर सरकार को सैकड़ो करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाई थी. धनेली की जमीन पर फर्जी होलोग्राम को नोएडा से लाकर भंडारण, डिस्टलरियों को वितरण, खाली शीशी डिसलरों को सप्लाई और अवैध शराब (पार्ट बी) के बिक्री से प्राप्त कमीशन का संग्रह किया जाता था. इस मामले पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 420, 468, 467, 471, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है.

आरोपियों के विरुद्ध 2500 पन्ने का चालान पेश– ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों के विरुद्ध आज 2500 पन्नों का चालान पेश किया गया है. इस चालान में आरोपियों से जुड़े नकली होलोग्राम मामले के करोड़ों रुपयों के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं. इस पूरे प्रकरण पर अन्य आरोपियों के विरुद्ध जांच चल रही है. जल्द अन्य आरोपियो के विरुद्ध चालान पेश कर कार्रवाई की जाएगी. ईओडब्ल्यू के वकील सौरभ पांडे ने बताया की आरोपियों के विरुद्ध नकली होलोग्राम मामले में आज 2500 पन्नों का चालान पेश किया गया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय 4 नवंबर को तय किया है.

बस्तर के चित्रकोट और ढूढमारस गांवों को मिला विशेष सम्मान

रायपुर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया है। बस्तर के चित्रकोट और ढूढमारस गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया। चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और ढूढमारस को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जाँच समिति का गठन

रायपुर। बालोद जिला अंतर्गत विकासखंड गुरुर के बडहूम एरिया ग्राम पेटेचुवा (चंद्राकर पोल्ट्री फार्म) में 7 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले को गंभीरता से लेते हुए आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल साहू जी ने प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय दुर्गा झा जी के अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया है जो निम्नानुसार है- 1. दुर्गा झा, 2. के ज्योति, 3. हरेश चक्रधारी, 4. पूर्णिमा सिन्हा, 5. चौवेन्द्र साहू, 6. कांता गरिहा 7. दीपक अरदे, 8. दुर्गेश्ला श्रीदेवी, 9. बालक साहू, 10. किरण साह, 11. चंद्रहास साहू।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. नाबालिग पीड़िता को अपने घर से बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत पेंड्रारोड ने 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को हुई भारतीय दंड सहिंता की धारा 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारवास और 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड के साथ धारा 5-सहपठित धारा 06 लैंगिक अपराध बालक संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है. दुष्कर्म आरोपी के साथी को भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

मुख्यमंत्री के काफिले की दो गाड़ियां टकराई

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले में चल रही दो गाड़ियां आपस में टकरा गई. यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री दुर्ग में विकास कार्यों का लोकार्पण कर पटेल चौक होते हुए सर्किट हाउस जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में अचानक आई गाय को बचाने के चक्कर में काफिले में चल रही दो गाड़ियां आपस में टकरा गई. दुर्घटना के बाद दो गाड़ियां काफिले में तत्काल बदल गई और उन गाड़ियों को मुख्यमंत्री के काफिले के साथ रवाना किया गया. मुख्यमंत्री साय के सुरक्षाकर्मियों को तत्काल इसकी सूचना दे दी. सीएम साय को सुरक्षा एसपी लाल उमेद सिंह ने इस घटना की सूचना दी.

राज्य सरकार गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित- साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग नगर के वार्ड नंबर-03 मठपारा में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण, साईस कॉलेज से रेलवे स्टेशन केनाल रोड सड़क चौड़ीकरण, चण्डी मंदिर से नया पारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की। उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की। सांसद एवं स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 22 करोड़ 97 लाख रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांवों के साथ-साथ शहरों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में एक साथ लगभग 23 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों का एक साथ भूमिपूजन किया गया, यह विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की झलक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करके आम जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीते 9 माह पर नजर डाले तो राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कम समय में बहुत से उल्लेखनीय काम किए हैं।

यह न्याय नहीं पश्चाताप यात्रा है

रायपुर। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने इस यात्रा को पश्चाताप यात्रा बताया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि, सरकार में आने पर कांग्रेस के 5 साल जो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, यह उसी की पश्चाताप यात्रा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को माफ नहीं किया, इसीलिए घर बिठा दिया। उल्लेखनीय है कि, 27 सितंबर शुक्रवार से कांग्रेस ने गिरौदपुरी से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के नाम से पदयात्रा शुरू की है। यह यात्रा 2 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में समाप्त होगी। वहीं न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि, राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। पहले बलौदाबाजार में हिंसा का मामला सामने आया, अब कवर्धा में साहू समाज के तीन लोगों की हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है। अभी बलौदाबाजार से यात्रा निकाली है, आगे अन्य स्थानों से भी यात्रा निकलेगी। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा- छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की आज शुरुआत हुई है। कार्यकर्ताओं में पहले पड़ाव में जबरदस्त उत्साह है। 6 दिन की यात्रा छत्तीसगढ़ के लिए क्रांति लाएगी। सरकार की नाकामी आम जनता तक यात्रा से पहुंचाएंगे।

राज्य में 700 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन लंबित

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभाग प्रमुखों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया है। जीएडी ने कहा कि यदि तृतीय श्रेणी में पद न हो तो चतुर्थ श्रेणी में भर्ती की जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी इस पत्र में जिलों से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि 7 अगस्त की स्थिति में राज्य के 32 जिलों में 872 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन लंबित हैं। इसमें तृतीय श्रेणी के 544 और चतुर्थी श्रेणी के पदों के लिए 238 आवेदन शामिल हैं। जीएडी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत की सीमा बंधन लागू है। ऐसे में यदि तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न हों, तो आवेदक को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदक के स्तर से आवेदन लंबित है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जाए।

पॉवर कंपनी के टेबल टेनिस में रायपुर सेंट्रल की टीम रही विजेता

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की कला एवं क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में आयोजित अंतरक्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रायपुर सेंट्रल और दुर्ग क्षेत्र के बीच खेला गया। इस टीम इवेंट में रायपुर सेंट्रल क्षेत्र की टीम विजेता और दुर्ग क्षेत्र की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह कल 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे होगा। इसमें पॉवर कंपनीज के प्रबंध निदेशक जनरेशन श्री एसके कटियार विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

पॉवर कंपनी के डंगनिया मुख्यालय स्थित खेल परिसर में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल और टीम इवेंट के मैच हुए। खिलाड़ियों ने चुस्ती-फुर्ती के साथ खेल का प्रदर्शन किया। टीम इवेंट का फाइनल मुकाबले में रायपुर सेंट्रल ने दुर्ग को 3-1 से हराया। रायपुर सेंट्रल के खिलाड़ी सर्वश्री प्रशांत बापट, अनिल अग्रवाल, अनुराग शर्मा, सागर पिपलापुरे और खिलेंद्र ने बेहतर प्रदर्शन किया। दुर्ग क्षेत्र के खिलाड़ी तरूण कुमार ठाकुर, पीएल महेश्वरी, महेश्वर टंडन, महेंद्र कुमार एवं रजनीश ओबेराय ने भी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया।

क्षेत्रीय क्रीड़ा सचिव विनय चंद्राकर ने बताया कि महिला वर्ग के डबल्स मुकाबले में रायपुर क्षेत्र की दिव्या आमदे और यशोदा रौतिया विजेता रहीं। श्रद्धा वर्मा व शोभना सिंह की जोड़ी उपविजेता रही।

इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के आठ क्षेत्रीय टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, मड़वा के साथ रायपुर सेंट्रल व रायपुर रीजन की टीम शामिल हैं।

28 सितंबर को पुरुष वर्ग के सिंगल और डबल के फाइनल व महिला वर्ग के सिंगल मुकाबले होंगे।

प्रदेश में 26000 से अधिक सूचना अधिकार के द्वितीय अपील के आवेदन लंबित

तत्काल मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो

रायपुर। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने व पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्तों के न होने कारण, द्वितीय अपील के लगभग 26 हजार आवेदन लंबित हो गये है। जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारीयो के हौसले बुलंद हैं ।

उन्होंने राज्य सरकार पर सूचना का अधिकार समाप्त करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा है, कि छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे अरसे से रिक्त हैं । मात्र दो सेवानिवृत नौकरशाहो को सुचना आयुक्त बना दिया गया है ,जबकि सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ दो और सूचना आयुक्त नियुक्त किये जा सकते है । ठाकुर ने प्रदेश के राज्यपाल महोदय से इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त कि नियुक्ति के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें । क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना अधिकार एक मात्र सहारा है ,जो पीड़ितों को न्याय दिला सकता है । लेकिन राज्य सरकार की इस मामले में अनदेखी के कारण हजारों अपीलार्थी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं । ठाकुर ने कहा कि न्याय की अवधारणा है कि समय पर न्याय न मिलना भी अन्याय के समान है। राज्य सरकार की भ्रष्टाचारियों के प्रति यह सहानुभूति समझ से परे है । अब हज़ारों पीड़ितों व अपीलार्थीयो के लिए राज्यपाल ही एक मात्र सहारा है । वे पहल करेंगे तो तत्काल मुख्य सूचना आयुक्त के साथ ही कम से कम दो और सूचना आयुक्तो की नियुक्ति राज्य सरकार करने को बाध्य हो जाएगी ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.